RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

वर्ष-08, अंक - 40 (साप्ताहिक) खवासा, गुरूवार 23 जुलाई 2026 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

सुविचार

सच्चा धर्म वही है जो स्वतंत्रता को परम मूल्य की तरह स्थापित करे।

शहीद चन्द्रशेखर आजाद

मोदी सरकार के खिलाफ पहली बार इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

दिल्ली। कोर्ट की तल्ख टिप्पणी कैसे आहत होकर गठित की गई कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने मोदी सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। जिसमें कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के शामिल होने के बाद इसे मोदी सरकार के खिलाफ लिए गए अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन बतलाया जा रहा है। नीट पेपर लीक के खिलाफ संसद मार्च के दौरान छात्रों पर किए गए लाठी चार्ज के बाद देश की राजनीति गरमा गई है सीजेपी की मुख्य मांग है कि, नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए।

क्योंकि नीट परीक्षा कराने की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और मंत्री होने के नाते नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही प्रदर्शन का समर्थन कर अनशन पर बैठे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर लगे प्रतिबंधों को हटाकर उन्हें तत्काल रिहा करने और पेपर लीक विवाद के कारण आत्महत्या करने वाले सभी छात्रों के परिवारों को एक करोड़ का मुआवजा दिए जाने की मांगा है। छात्रों द्वारा शांतिपूर्ण मांग और संसद मार्च के दौरान किए गए लाठी चार्ज के खिलाफ पूरे देश के युवाओं की आक्रोश भरी प्रतिक्रियाए सामने आ रही है। कोई इसे सरकार की तानाशाही बतला रहे है तो कोई इस आंदोलन की तुलना अन्ना आंदोलन से कर रहा है। पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ युवाओं का आक्रोश पहली बार देखने को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस नेता और राहुल गांधी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद देशभर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भी सरकार के खिलाप प्रदर्शन किया जा रहा है। वही सोशल मीडिया पर युवाओं की तल्ख और व्यवस्था विरोधी टिप्पणियों की बाढ़ आ गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह बयान भी युवाओं के आक्रोश को ठंडा नहीं कर पाया है जिसमें उन्होंने पेपर लीक की घटना में दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कही है। युवाओं का कहना है कि, पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान को सरकार आखिरकार क्यों बचाना चाहती है।

इसी बीच वांगचूक से मिलने पहुंचे विपक्षी सांसदों को पुलिस ने रोका जिसके बाद वे मेदांता अस्पताल के गेट पर धरने पर बैठ गए हैं। वहीं वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को कहा है कि, सरकार अगर बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन न लेने का भरोसा दे तो वे अनशन समाप्त कर सकते हैं।

वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार की तरफ से बातचीत की पेशकश पर कहा है कि, हम किसी मंत्री के घर बात नहीं करेंगे किसी तटस्थ स्थान पर बातचीत को तैयार है। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का आज 33वाँ दिन है। बुधवार सुबह से हजारों प्रदर्शनकारी मौजूद है दिल्ली हाई कोर्ट ने छात्रों से मारपीट के मामले की सुनवाई में। सरकार से कहा है कि, मारपीट के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाए सरकार के खिलाफ देशभर में हुए प्रदर्शन के बाद सड़क से संसद तक छात्रों से की गई मारपीट को सरकार द्वारा की गई बर्बरता कहा जा रहा है। और मामले की जांच के साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी की मांगों को तत्काल सरकार से पुरी की जाने की मांग देशभर में भी की जा रही है।

समान नागरिक संहिता लागू करने वाला चौथा राज्य बना मध्य प्रदेश

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

भोपाल। मध्य प्रदेश में मानसून सत्र के दूसरे दिन समान नागरिक संहिता यूसीसी समेत 8 बिल पास हो गए। यूसीसी बिल पारित करने वाला चौथा राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। इससे पहले उत्तराखंड, गुजरात और असम की विधानसभाओ में यह बिल पास हो चुका है। अब यह बिल राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा। इस बिल का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी नागरिक को धर्म और समुदायों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों से जुड़े मामलों में एक समान कानून लागू करना है।

इस बिल के मुख्य प्रावधान है विवाह और तलाक के नियम के अंतर्गत सभी धर्मों के लिए केवल एक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई और बहु विवाह पूर्णत प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही विवाह पंजीकरण भी अनिवार्य किया गया है। 23 सितंबर 2008 से यूसीसी बिल लागू होने तक हुए ऐसे सभी विवाह जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है उनका पंजीकरण एक वर्ष के भीतर कराना होगा। 2008 के पहले हुए विवाह का पंजीयन स्वैच्छित होगा। साथ ही यूसीसी बिल लागू होने के बाद भी अगर कोई विवाह पंजीकरण नहीं करवाता है तो रजिस्ट्रार नोटिस जारी करेगा और उसके बाद 25 हजार तक जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन सिर्फ पंजीयन के अभाव में विवाह को अवैध नहीं माना जाएगा। मौखिक तलाक, तीन तलाक, और निकाह हलाला को गैर कानूनी और दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण भी अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही विवाह होते हुए भी किसी अन्य के साथ लिव इन में रहने पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। पंजीकृत लिव इन से पैदा हुए बच्चों को कानूनी वैधता और संपत्ति का सम्मान अधिकार भी इस विधेयक में दिया गया है। संपत्ति के उत्तराधिकार मामलों में लेगिंग भेदभाव सम्मान कर दिया गया है, यानी बेटे और बेटियों को संपत्ति में सम्मान अधिकार प्राप्त होंगे। इसके साथ ही संविधान के अंतर्गत विशेष संरक्षण प्राप्त अनुसूचित जनजातियों और कुछ पारंपरिक समुदायों को इस कानून के दायरे में बाहर रखा गया है।

इसके साथ ही अन्य विधेयक भी पास किए गए हैं उनमें आम जनता से जुड़े मुख्य विधेयक है मध्य प्रदेश राजमार्ग विधेयक, जिसमें सरकार स्टेट हाईवे पर यूजर चार्ज लगा सकती है और किसी भी सड़क को राजमार्ग घोषित कर सकती है। इससे लगी जमीन के उपयोग को नियंत्रित कर सकती है, अतिक्रमण रोक सकती है और जरूरत पड़ने पर यूजर चार्ज भी लगा सकती है। अभी तक राज्य सरकार के पास स्पष्ट कानूनी अधिकार नहीं था।

मध्य प्रदेश कार्य स्थल सशक्तिकरण संहिता विधेयक (श्रम संहिता विधेयक) इसके अंतर्गत 24 घंटे दुकान और प्रतिष्ठा खुल सकेंगे लेकिन प्रति 8 घंटे में ड्यूटी बदला जाता अनिवार्य होगा। सप्ताह में 6 दिन में 48 घंटे की ड्यूटी तय होंगी जो आपसी सहमति से कर्मचारी और मालिक तय कर सकेंगे। संस्थाओं के लिए एक बार का डिजिटल पंजीकरण लागू किया गया है और नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के मूल दस्तावेजों को अपने पास बंधक रखने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। महिला सुरक्षा के लिए कार्य स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रावधान है। उबर, जोमेटो या अन्य प्लेटफार्म पर काम करने वाले श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है।

फायर सर्विस के लिए नया सर्विस केंद्र गठित करने का विधेयक भी पास किया गया है जिसका संचालक नगरीय निकाय करेंगे तथा निगरानी राज्य सरकार करेगी। नया सर्विस केंद्र गठित होने के बाद दमकल सेवाएं पुलिस थानों की तर्ज पर काम करेगी और आपातकालीन स्थिति में शहरी क्षेत्र में 10 मिनट तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनट में दमकल गाड़ीयो को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही बिना फायर एनओसी के भवनो का उपयोग करने पर 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।

भारी बारिशः केदारनाथ मार्ग पर गिरे पत्थर और बोल्डर, यात्रा अस्थायी रूप से रोकी

रुद्रप्रयाग।

लगातार हो रही वर्षा का असर केदारनाथ यात्रा पर पड़ा है। गौरीकुण्ड से लगभग एक किलोमीटर आगे छौड़ी क्षेत्र में केदारनाथ पैदल मार्ग पर अचानक बड़े पत्थर, बोल्डर और मलबा गिरने से मार्ग बाधित हो गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यात्रियों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी है तथा उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार देर रात हुई वर्षा के कारण पहाड़ी से बड़े पत्थर और मलबा खिसककर मार्ग पर आ गया, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस, राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) तथा संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंच गईं। मार्ग से मलबा और बोल्डर हटाने का कार्य जारी है।

प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी कारण गौरीकुण्ड और मार्ग के विभिन्न पड़ावों पर यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। अधिकारी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं तथा मौसम की परिस्थितियों पर भी नजर रखी जा रही है।

वर्षा के कारण केदारघाटी में भूस्खलन की आशंका बनी हुई है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल प्रशासन तथा मौसम विभाग द्वारा जारी आधिकारिक निर्देशों का पालन करें। साथ ही निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन करें।

प्रशासन के अनुसार मौसम सामान्य होने और मार्ग पूरी तरह साफ होने के बाद ही यात्रियों को आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। राहत एवं बचाव दल लगातार कार्य में जुटे हुए हैं ताकि शीघ्र मार्ग बहाल कर यात्रा को सुचारु रूप से संचालित किया जा सके। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई गई है।

असमः बाढ़ से 21 की मौत, कई गांव डूबे, 5.64 लाख लोग प्रभावित

गुवाहाटी।

असम में बाढ़ के कारण पिछले 24 घंटों में 21 और लोगों की मौत हो गई, जबकि राज्य के 16 जिलों में 5.64 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। यह जानकारी असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) द्वारा जारी बुलेटिन में दी गई है।

बुलेटिन के अनुसार सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर जिले में 13 लोगों की मौत हुई है। चराइदेव में पांच, गोलाघाट में दो और जोरहाट में एक व्यक्ति की जान गई। इसके साथ ही इस वर्ष राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है।

मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि वह आज से बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे।

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ से गोलाघाट, कामरूप, होजाई, डिब्रूगढ़, बिश्वनाथ, धेमाजी, सोनितपुर, उदालगुड़ी, नगांव, चराइदेव, कामरूप महानगर, जोरहाट, तिनसुकिया, कार्बी आंगलोंग, लखीमपुर और शिवसागर सहित 16 जिलों में 5,64,600 से अधिक लोग प्रभावित हैं। एक दिन पहले 15 जिलों में प्रभावित लोगों की संख्या 3.63 लाख से अधिक थी।

बुलेटिन के मुताबिक 44 राजस्व मंडलों के 872 गांव अब भी जलमग्न हैं। सबसे अधिक 3,59,535 लोग शिवसागर जिले में प्रभावित हैं। इसके बाद जोरहाट में 87,662 और चराइदेव में 72,646 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।

पाकिस्तानः बढ़ी गरीबी, हर 10 में से लगभग 3 गरीबी रेखा के नीचे

इस्लामाबाद।

गंभीर आर्थिक संकट और लगातार बढ़ती महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान में आम लोगों की स्थिति लगातार कठिन होती जा रही है। देश में आर्थिक मंदी का प्रभाव अब आंकड़ों में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हालिया सर्वेक्षणों के अनुसार पाकिस्तान में लगभग 28.9 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, अर्थात हर 10 में से लगभग 3 लोग गरीबी से प्रभावित हैं।

घरेलू एकीकृत आर्थिक सर्वेक्षण तथा पाकिस्तान सामाजिक एवं जीवन स्तर मापन सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में देश की गरीबी दर 21.8 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 28.9 प्रतिशत हो गई है। छह वर्षों के दौरान गरीबी में हुई यह वृद्धि आर्थिक चुनौतियों की गंभीरता को दर्शाती है।

आंकड़ों के अनुसार आर्थिक संकट का सबसे अधिक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ा है। गांवों में गरीबी की दर शहरों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ी है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानता और बढ़ गई है। पिछले छह वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दर में लगभग 8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह बढ़ोतरी लगभग 6 प्रतिशत अंक रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार आर्थिक संकट, कोविड-19 महामारी के प्रभाव, खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और कड़े आर्थिक सुधारों का सबसे अधिक बोझ गरीब वर्ग पर पड़ा है। उनका कहना है कि महंगाई की तुलना में परिवारों की आय और क्रय क्षमता में लगातार गिरावट आई है।

विश्लेषकों के अनुसार विकास संबंधी दावों के बावजूद आम पाकिस्तानी परिवारों की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है और बड़ी आबादी आज भी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है।

सोनम वांगचुक के समर्थन में अमेरिका से यूरोप तक प्रदर्शन

न्यूयॉर्क/नई दिल्ली।

शिक्षा सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन मिलने लगा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क और सैन होजे सहित यूरोप के लंदन, बर्लिन, नीदरलैंड और आयरलैंड में भारतीय मूल के लोगों तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर शिक्षा व्यवस्था में सुधार और कथित परीक्षा अनियमितताओं पर जवाबदेही की मांग उठाई।

अमेरिकी संगठन 'हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स' के बैनर तले न्यूयॉर्क के यूनियन स्क्वायर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष तथा सैन होजे में प्रदर्शन आयोजित किए गए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर सोनम वांगचुक के समर्थन में नारे लगाए और केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।

संगठन के अनुसार इसी प्रकार के एकजुटता प्रदर्शन लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग और डबलिन स्थित भारतीय दूतावास के बाहर भी आयोजित किए गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भारत के विद्यार्थियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय शिक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए। साथ ही सरकार को छात्रों की चिंताओं पर खुला संवाद शुरू कर आवश्यक सुधार लागू करने चाहिए।

उल्लेखनीय है कि सोनम वांगचुक शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों और कथित परीक्षा अनियमितताओं को लेकर लंबे समय से अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें जंतर-मंतर से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर उनका उपचार जारी है।

इस बीच देश के कई विपक्षी दलों ने भी उनके समर्थन में प्रदर्शन किए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते समर्थन को शिक्षा सुधार की मांग को वैश्विक स्तर पर मिल रही सहानुभूति के रूप में देखा जा रहा है।

इंद्र देवता को मनाने के लिए तरह-तरह के जतन, गत वर्ष से आधी भी नहीं हुई बारिश

माही की गूंज, पेटलावद।

बारिश की बेरुखी ने किसानों के साथ-साथ आम जनता को चिंतित कर दिया है। किसानों की फसल बारिश की देरी के चलते पहले ही लगभग 20 से 30 दिन लेट हो चुकी हैं। बारिश के पहले दौर के बाद उम्मीद थी कि, अब वर्षा चक्र सही चलता रहेगा लेकिन किसानों की उम्मीदों पर इंद्र देवता की बेरुखी ने पानी फेर दिया। बारिश की लंबी खेच ओर मानसून की बेरुखी के चलते अब अच्छी बारिश ओर रूठे इंद्र देवता को मनाने के लिए लोगो ने तरह-तरह के टोन टोटके का सहारा लिया ताकि अच्छी बारिश हो ओर खेत में बोई हुई फसल अच्छी हो सके।

जिंदा व्यक्ति की निकली अर्थी, गधे पर उल्टा बैठा निकला जुलूस, जगह जगह उज्जैनी

वर्षा की लंबी खेच ने लोगो को तरह-तरह के टोटके आजमाने पर मजबूर कर दिया। उज्जैनी मनाने का दौर विकास खंड के लगभग हर गांव में हो चुका हैं। जबकि लोग नए-नए टोटके भी बारिश के लिए अपनाया। रविवार को पेटलावद में लोगो ने जिंदा व्यक्ति की अर्थी निकाल ली। लोगो ने राम नाम सत्य के उदघोष के साथ जिंदा व्यक्ति की अर्थी पूरे नगर में घुमाई इसके बाद श्मशान पर ले जाकर आंशिक अंतिम संस्कार कर अच्छी बारिश की कामना की। वही मंगलवार को भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला जिसमें संपूर्ण रायपुरिया बंद रख सभी रायपुरिया व्यापारी बंधु अपने-अपने प्रतिष्ठान बंद कर घर में चूल्हे नहीं जलाए एवं खेतों पर खाना बनाकर उज्जैनी मनाई गई। साथ ने नगर में एक व्यक्ति को गधे पर उल्टा बैठा कर गाव में घुमाया गया। कहा जाता है इस प्रकार के टोटकों से बारिश हो जाती हैं। भोले शंभू भोल नाथ जल बरसा दो दिना नाथ के उदघोष के साथ कई गांवों में लोग अच्छी बारिश के लिए प्रभात फेरी भी निकाल कर इंद्र देवता को मनाने का प्रयास कर रहे है।

गत वर्ष से आधी वर्षा भी नहीं

इस बार मानसून की बेरुखी शुरुवात से ही बनी हुई, बारिश शुरू होने के बाद वापस रुकी और फिर वर्षा का दौर थम सा गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष बारिश अभी तक गत वर्ष से आधी भी दर्ज नहीं हुई है। सावन माह आने को है ओर लोग अब भी अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहे है। वही मानसुन विभाग आज 22 से 26 जुलाई के बिच बारिश होने की बात कर रहा है।

राहुल, प्रियंका की गिरफ्तारी के विरोध में रात में ही धरने पर बैठ गए कांग्रेसी

माही की गूंज, पेटलावद।

दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दलों के नेता, राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठ गए। देखते ही देखते बड़े नेताओं को फौज राहुल गांधी के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंच गए। राहुल गांधी के साथ मुख्य रूप से उनकी बहन सांसद प्रियंका गांधी और सपा नेता अखिलेश यादव मुख्य रूप से मौजूद रहे। सरकार को ओर से धरना समाप्त करने के लिए बातचीत की गई लेकिन कांग्रेस ओर दूसरे नेता धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहे, आखिर पुलिस ने राहुल ,प्रियंका समेत कई नेताओं को धरना स्थल से उठा लिया। जैसे ही खबर फैली जगह जगह कांग्रेस नेता रात में ही सड़को पर उतर गए ओर केंद्र सरकार की कार्यवाही का कड़ा विरोध दर्ज करवाया। पेटलावद में ही दिल्ली की हवा पहुंची और यहां किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अकमांल मालू के नेतृत्व में भाजपा ओर केंद्र सरकार के खिलाफ जम कर नारे बाजी करते हुआ तहसील कार्यालय में धरने पर बैठ गए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्य मार्ग पर अलग अलग जगहों पर नारेबाजी कर भाजपा ओर सरकार की कार्यवाही को विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाते रहे। जिला पंचायत उपाध्यक्ष अकमाल मालू ने कहा को केंद्र सरकार को अपनी गलती मानते हुए नीट पेपर लिक के कारण कई बच्चों की जान की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में देश के युवाओं की आवाज उठाई जा रही हैं,जिसे केंद्र सरकार द्वारा दबाया जा रहा है। राहुल ,प्रियंका समेत सभी नेताओं को छोड़ने की खबर आने के धरना समाप्त किया गया।

डेंगू निरोधक : जन-जागृति प्रचार रथ रवाना

माही की गूंज, झाबुआ।

प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी जुलाई माह को डेंगू निरोधक माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एम.एल. चौपड़ा द्वारा डेंगू, चिकनगुनिया एवं मलेरिया जैसी मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम एवं जन-जागरूकता के उद्देश्य से प्रचार-प्रसार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह प्रचार रथ जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर आमजन को मच्छरजनित रोगों से बचाव के उपायों की जानकारी देगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि, वर्षाकाल में डेंगू, चिकनगुनिया एवं मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। डेंगू का मच्छर घरों के अंदर एवं आसपास एक सप्ताह से अधिक समय तक रुके हुए स्वच्छ पानी में पनपता है। खुले पानी के टैंक, पुराने टायर, कूलर, फ्रिज की ट्रे, फूलदान, गमले तथा अनुपयोगी बर्तनों में जमा पानी डेंगू के मच्छरों के प्रजनन का प्रमुख स्रोत बनता है। यह मच्छर दिन के समय काटता है तथा लगभग 400 मीटर तक उड़ सकता है।उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि बुखार आने पर स्वयं उपचार करने के बजाय तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर चिकित्सकीय परामर्श लें तथा आवश्यकतानुसार रक्त जांच कराएं। साथ ही घरों एवं आसपास पानी जमा न होने दें। पानी की टंकियों, कूलरों, हौदियों, कंटेनरों एवं फ्रिज की ट्रे को सप्ताह में कम से कम एक बार खाली कर साफ करें तथा उन्हें सदैव ढंककर रखें। छतों एवं घर के आसपास पड़े पुराने टायर, गमले, फूलदान एवं अन्य अनुपयोगी पात्रों में पानी जमा न होने दें।

मच्छरों से बचाव के लिए घर एवं आसपास साफ-सफाई बनाए रखें, खिड़कियों एवं दरवाजों पर मच्छरजाली लगवाएं, पूरी बांह के कपड़े पहनें तथा सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि, डेंगू की पुष्टि के लिए एलाइजा जांच जिला चिकित्सालय झाबुआ में निःशुल्क उपलब्ध है। नागरिक किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर समय पर जांच एवं उपचार कराकर स्वयं तथा अपने परिवार को सुरक्षित रखें।

15 अगस्त की तैयारियों की समीक्षा, अधिकारियों को सौंपे दायित्व

माही की गूंज, झाबुआ।

कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आगामी स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय समारोह की तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में समारोह के गरिमामय एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि स्वतंत्रता दिवस समारोह की सभी तैयारियां समय-सीमा में पूर्ण की जाएं तथा प्रत्येक विभाग अपने निर्धारित दायित्वों का गंभीरता एवं समन्वय के साथ निर्वहन सुनिश्चित करे। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर बैठक व्यवस्था, साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत, पार्किंग, सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा, यातायात व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में ध्वजारोहण समारोह, परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुरस्कार वितरण, विभागीय समन्वय एवं अन्य व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा सभी व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

बस किराया वृद्धि को लेकर निर्णायक तैयारी

भोपाल।

मध्यप्रदेश में बस किराया वृद्धि की मांग को लेकर बस संचालकों ने निर्णायक रणनीति बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। किराया संशोधन को लेकर लंबे समय से मांग किए जाने और लगातार आश्वासन मिलने के बावजूद निर्णय नहीं होने से नाराज मध्यप्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन ने 26 जुलाई को सागर में प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई है।

एसोसिएशन के अनुसार बैठक में प्रदेश के सभी 55 जिलों से कम से कम पांच-पांच प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें किराया वृद्धि, 7 जुलाई को प्रकाशित राजपत्र में राष्ट्रीयकरण योजना तथा बस संचालकों से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

एसोसिएशन के महामंत्री जय कुमार जैन ने बताया कि बैठक सागर के भोपाल रोड स्थित आदर्श गार्डन में दोपहर एक बजे आयोजित की जाएगी। प्रदेशभर के बस संचालकों की उपस्थिति में सरकार के रुख की समीक्षा की जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन और प्रदेशव्यापी हड़ताल की रूपरेखा भी तैयार की जा सकती है।

बस संचालकों का कहना है कि परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के साथ कई दौर की चर्चा में किराया वृद्धि का आश्वासन मिला था, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इस बीच डीजल, कल-पुर्जों, बीमा, वाहन फिटनेस, टायर तथा अन्य परिचालन व्यय में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे बस संचालन आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है।

एसोसिएशन का कहना है कि पड़ोसी राज्यों में भी किराए का पुनरीक्षण किया जा चुका है। हाल ही में महाराष्ट्र में भी बस किराए में वृद्धि की गई है। ऐसे में मध्यप्रदेश में लंबे समय से किराया दरों में संशोधन नहीं होने के कारण बस संचालकों पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है।

बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि यदि सरकार शीघ्र किराया वृद्धि पर निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन को किस स्वरूप में आगे बढ़ाया जाए। प्रदेशभर के बस संचालकों की नजर अब इस बैठक पर टिकी हुई है, क्योंकि यहीं से आगे की रणनीति और संभावित आंदोलन की दिशा तय होने की संभावना है।

तांत्रिक के पास इलाज कराने पहुंची महिला के साथ रेप

माही की गूंज, धार/कुक्षी।

जिले के कुक्षी थाना क्षेत्र में तांत्रिक क्रिया के नाम पर महिला से दुष्कर्म किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर एक कथित तांत्रिक सहित चार आरोपियतो के विरुद्ध दुष्कर्म, सामूहिक अपराध में सहभागिता, अवैध रूप से रोकने और धमकी देने सहित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। सभी आरोपित फिलहाल फरार बताए गए हैं।

पुलिस के अनुसार पीड़िता ने शिकायत में बताया कि 25 मार्च 2026 को उसे बवासीर का तांत्रिक उपचार कराने का झांसा देकर मनावर बस स्टैंड से पिपलिया गांव ले जाया गया। वहां एक मकान के ऊपरी कमरे में कथित तांत्रिक के पास छोड़कर अन्य आरोपी बाहर निकल गए। आरोप है कि कमरे में मौजूद कथित तांत्रिक ने तांत्रिक क्रिया का हवाला देते हुए महिला से आंखें बंद कर चुपचाप बैठने को कहा और इसी दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया।

तंत्र क्रिया से पति की जान लेने की धमकी दी

पीड़िता का आरोप है कि घटना के बाद जब उसने अन्य आरोपियों को पूरी बात बताई तो सभी ने किसी को भी घटना की जानकारी देने पर तांत्रिक क्रिया के माध्यम से उसे और उसके पति को जान से मरवाने की धमकी दी। भय के कारण वह तत्काल पुलिस तक नहीं पहुंच सकी। बाद में पति को घटना की जानकारी देने के बाद उसने हिम्मत जुटाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई।

कुक्षी पुलिस ने कथित तांत्रिक कैलाश निवासी खण्डलई तथा राकेश, रेवसिंह और धन्नालाल के विरुद्ध बीएनएस की धारा 64(1), 70(1), 127(1) और 351(3) सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं में मामला दर्ज किया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक रवि वास्के को सौंपी गई है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।

भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ किया प्रदर्शन

भोपाल।

दिल्ली में राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री आवास के घेराव के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ विधायक रामेश्वर शर्मा और भगवानदास सबनानी सहित अन्य नेताओं ने किया।

विरोध जताने के लिए पार्टी नेताओं ने काले वस्त्र धारण कर कांग्रेस की रणनीति के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और उसकी नीतियों की आलोचना की। राजनीतिक गलियारों में प्रदर्शन के तौर-तरीकों और घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं भी होती रहीं। एक ओर भाजपा का आक्रामक रुख देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने गुलाब के गुलदस्ते के साथ अलग रणनीति अपनाते हुए भाजपा नेताओं का स्वागत किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस की आक्रामक राजनीति के जवाब में भाजपा भी अब सड़क पर उतरकर सक्रिय विरोध प्रदर्शन के माध्यम से अपनी रणनीति को धार देने में जुटी है।

बाल विवाह प्रतिषेध, अधिकारियों का प्रशिक्षण

माही की गूंज, झाबुआ।

मिशन शक्ति अंतर्गत बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत यूनिसेफ एवं ममता संस्था के तकनीकी सहयोग से शासन द्वारा अधिसूचित बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के रूप में नामित लगभग 200 पटवारी एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के सुपरवाइजरों ने सहभागिता की।

कार्यशाला का उद्देश्य बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की क्षमता का विकास करना, बाल विवाह की रोकथाम के लिए उनकी भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाना तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करना था।

प्रशिक्षण के दौरान यूनिसेफ के बाल संरक्षण अधिकारी गोविंद बेनीवाल एवं सलाहकार अमरजीत कुमार सिंह ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रमुख प्रावधानों, बाल विवाह के सामाजिक, शैक्षणिक एवं कानूनी दुष्परिणामों तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों के अधिकारों, कर्तव्यों एवं दायित्वों पर विस्तृत जानकारी दी।

डेढ़ दशक के बाद दिगम्बर संतों का हुआ मंगल प्रवेश

माही की गूंज, थांदला।

17 वर्ष बाद आचार्य श्री 108 कुंथुसागरजी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना तपोनिधि आचार्य 108 श्री कुशाग्रनन्दीजी महाराज, 108 श्री अजयऋषिजी महाराज, 105 गणिनी आर्यिका जिनवाणी माताजी, 105 गणिनी आर्यिका कीर्तिवाणी माताजी, 105 छुल्लिका श्री विनम्रज्योती माताजी, 105 छुल्लिका की अचलज्योतिजी माताजी, 105 छुल्लिका पुण्यभारती माताजी, 105 स्वस्ति डा. पद?म?कीर्ति स्वामीजी व संघस्थ ब्रम्हचारिणी आराधना दीदी व अमृतप्रिया दीदी सहित संघ का मंगल प्रवेश कुशलगढ़ रोड़ से हुआ। आचार्य श्री के भव्य मंगल प्रवेश हेतु श्रावक, श्राविका वर्ग के साथ युवा वर्ग एक सी वेशभूषा में नजर आए। संघजनों ने जयकारा के साथ बैंड-बाजों की भक्तिमय धुनों पर नाचते गाते व फूलों की वर्षा करते हुए नगर में प्रवेश करवाया। धर्म सभा का आयोजन करते हुए गुरुदेव श्री कुशाग्रनन्दीजी ने कहा कि, अनायास ही बहती गंगा थांदला आ गई है जिसमें सबको धर्म की डुबकी लगाना है। आचार्य श्री ने कहा पहले हम आपके कहने में आकर थांदला आ गए है।

अब आपको हमारा कहना मानना है जिससे आपके जीवन के सब दुःख दूर हो जायेगें। आपने कहा चातुर्मास काल में पहले संघ की पहचान होती है तो चातुर्मास के अंत में संत विहार के बाद संत की पहचान होती है। इसलिए आप सभी को जिस एकता आत्मीयता के साथ सकल संघ का प्रवेश करवाया उसी तरह अब पूरे चातुर्मास को भी दीखाना है। इस अवसर पर संघ अध्यक्ष अरुण कोठारी ने संघ कि ओर से आचार्य सहित नगर में पधारें सकल संत व आर्यिका माता आदि संघजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए थांदला से दीक्षित हुए संत-सतियों की जानकारी देते हुए इसे संत नगरी कहने की सार्थकता बतलाई। संचालन संघ पदाधिकारी संजय कोठारी व महिला मंडल अध्यक्षा अरुणा मेहता ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर संघ के वरिष्ठ कांतिलाल मेहता, राजेन्द्र पिण्डरमा, इन्द्रवर्धन मेहता, अनूप मिंडा, विजय भिमावत, पारस मेहता, देवेंद्र मेहता, दीपक पिंडरमा, शशिकांत बोबड़ा सहित सकल संघ के श्रावक-श्राविका युवा व बाल ने उपस्थित होकर जिन शासन के तपोनिध महान संतों को नमोस्तु कहते हुए उनकी सेवा सुश्रुषा की।

अवैध रेत विक्रेता व ब्याज खोरी का धंधा करने वाले का सहारा के एजेंट से विवाद

माही की गूंज, खवासा।

वैसे तो कोई भी अवैध कार्य न हो उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था बनी हुई है और नियमित रूप से अवैध कार्यों पर कार्रवाई करने का जिम्मा अधिकारियों पर है। लेकिन चाहे अवैध खनन हो, रेत का अवैध कारोबार हो, अवैध शराब की बात हो या फिर अवैध रूप से सूदखोरी का कारोबार हो ये सभी अवैध कार्य प्रशासनिक नुमाइंदों की नाक के नीचे बेधड़क हो रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर अपने टारगेट पूर्ति व किसी बड़ी शिकायत के बाद छूट-मूट कार्रवाई कर प्रशासन अपनी वाहवाही करता है।

खवासा व आसपास क्षेत्र में अवैध रेत बिक्री की बात करें तो सांदीपनी स्कूल परिसर के बाहर शासकीय जगह पर ही रेत का ढेर लगाकर बालू रेत की अवैध बिक्री की जाती है। दूसरा खवासा रोग्या देवी बाईपास पर रेत का ढेर कर अवैध रेत की बिक्री की जाती है। वहीं भामल में 8 वें लेन के ब्रिज के नीचे बड़ी मात्रा में रेत का ढेर लगाकर बालू रेत की बिक्री की जाती है। वहीं क्षेत्र के नाहरपुरा माही तट से मशीन से ट्रैक्टरों में छालना लगाकर रेत भरी जाती है जिसका रेत भराई का चार्ज 15 सौ रुपए मशीन संचालक लेते हैं।

कहने को यह रेत विक्रय व खनन पूरी तरह से बिना रॉयल्टी का होकर अवैध विक्रय है। लेकिन दूसरी और यह भी कहा जा सकता है कि, जब क्षेत्र में रॉयल्टी के साथ खदान नहीं होने के चलते भवन निर्माण में बिना रॉयल्टी की यह अवैध रेत ही नींव का पत्थर बन लोगों को सुविधा मिलती है। ऐसे में इन अवैध रेत विक्रेताओं के विरुद्ध न ही कोई शिकायत करता है और न ही कोई अब तक राजस्व व खनिज विभाग ने कोई बड़ी कार्रवाई की है।

वर्तमान में पिछले दिनों खवासा में अवैध रेत विक्रय की शिकायत को लेकर मामला यह सामने आया कि, रोग्यादेवी बाईपास पर रेत का ढेर लगाकर रेत बेचने वाला व्यापारी जिसने अपने पैतृक जमिन पर बने भवन पर परिसर में रेत के ढेर के साथ विज्ञापन लिखा कि, बालू रेत, ट्रॉली, डंपर, गिट्टी, डस्ट, जेसीबी के लिए संपर्क करें। प्रोपराइटर लोकेंद्र पिता गोवर्धनलाल चौहान मोबाइल नंबर 9755132531, 99810 56608 अंकित कर रखा था। शिकायत के बाद सामने आया कि स्थानीय मुकेश चौहान जो की पूर्व में सहारा समय का एजेंट था व दैनिक कलेक्शन कर उक्त संपूर्ण राशि सहारा समय कंपनी में जमा कर ग्राहकों को प्रति महीने के आखिरी में जमा राशि की रसीद सहारा समय की दे देता था। लेकिन कुछ अनियमितताओं के चलते सहारा समय की यह कंपनी बैंक क्रप्ट हो गई और जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वही सहारा समय की जमा अवधि खत्म होने के चलते एक दायरे में कम-कम राशि न्यायालय के माध्यम से एजेंटों को दी भी जा रही है। वही खवासा के मुकेश चौहान ने भी कई लोगों से दैनिक बचत एवं एफडी कर सहारा समय की जमा रशीदे दी गई।

विवाद का कारण यह रहा कि, करीब 16-17 वर्ष पूर्व 50 हजार के करीब की एफडी लोकेन्द्र चौहान के पिता ने अपने रिश्तेदार मुकेश चौहान से करवाई। चुंकि मुकेश चौहान अनुसार एफडीकर्ता का विश्वास पूर्ण रूप से सहारा समय कंपनी पर था लेकिन सहारा समय के एजेंट मुकेश चौहान पर नहीं था। एफडी करता का मानना था कि, कंपनी में जमा करने के पूर्व या अवधि पूर्ण होने पर कंपनी से आहरण करने के बाद एजेंट पैसा लेकर अपने पास नहीं रख ले। इस विश्वास की पूर्ति हेतु एफडीकर्ता ने एजेंट मुकेश चौहान से हस्ताक्षर वाला एक खाली चेक स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का लिया गया। और मुकेश चौहान ने यह चेक कंपनी द्वारा राशि मिलने पर संपूर्ण राशि एफडी करता को देने पर चेक लेने की बात कही।

वही इन वर्षों में बदलाव के चलते यह हुआ कि, सहारा समय बैंकक्रप्ट हो गई वहीं स्टेट बैंक आफ इंदौर का नाम भारतीय स्टेट बैंक में विलय हो गया।

मुकेश चौहान का कहना है कि, एफडीकर्ता हमारे रिश्तेदार ही है जो एफडी सहारा समय के नाम पर करवाई थी वह राशि मैने सहारा समय में जमा करवा दी और जमा एफडी की प्रतिलिपी भी जमा करता रिश्तेदार को दे दी गई। लेकिन सहारा समय बैंकक्रप्ट होने के चलते एफडी

शकायत के बाद राजस्व अधिकारी अवैध रेत का निरिक्षण करते हुए।

मालिक के पुत्र लोकेंद्र ने 50 हजार के करीब राशि को डेढ़ लाख रुपए मूल बताकर ढाई लाख के करीब का चेक बैंक में लगाने का प्रयास कर मुझे नोटिस देने का घृणित अपराध किया है।

मुकेश चौहान ने बताया कि, उक्त लोकेंद्र चौहान अवैध रेत विक्रेता होकर सुदखोर भी है। लोकेंद्र बिना किसी लाइसेंस के लोगों की मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर व ट्रॉली तक गिरवे रख मजबूर लोगों से बड़ी राशि वसूलता है।

मुकेश चौहान ने बताया कि, एक समाचार पत्र में उक्त अवैध रेत विक्रेता का समाचार प्रकाशन हुआ था जिसके बाद राजस्व अधिकारी भी मौके पर अवैध रेत का निरीक्षण करने पहुंचे थे। लेकिन समाचार छपने के बाद लोकेंद्र चौहान ने अपनी चार सौ बीसी फितरत्ती कर भवन पर लिखा उसका रेत-गिट्टी बेचने का विज्ञापन कलर करवाकर मिटा दिया गया। वहीं लोकेंद्र ने जांचकर्ता अधिकारियों को बताया कि, उक्त रेत का अवैध विक्रय नहीं कर निजी भवन निर्माण हेतु रेत लाई गई।

वहीं जब सचिव कांतिलाल परमार से बात की तो बताया, लोकेंद्र चौहान या उसके परिवार ने किसी ने भी पिछले तीन महीनो में भवन निर्माण की कोई परमिशन नहीं ली गई। न ही कोई भवन निर्माण का कार्य उनका चल रहा है। ऐसे में जांचकर्ता अधिकारी को जो भवन निर्माण की जानकारी दी गई वह झूठी व चार सौ बीसी है।

मुकेश चौहान का कहना है कि, एफडीकर्ता व उसका पुत्र चेक लगाकर कोर्ट में जाए तो वहां भी मेरे तथ्य पेश करूंगा। जो पैसा मैंने एफडी के लिए लिया था वह सहारा समय में जमा किया है न कि मेरे पास रखा है।

वही लोकेंद्र चौहान से जब मामले में बात की तो बताया, यह सही है कि सहारा समय में एफडी के नाम पर पिताजी से जो रूपए लिए थे व उसकी रसीद भी हमें दी है। लोकेंद्र चौहान ने फोन पर डेढ़ लाख की एफडी करना बताया व 15 वर्ष का ब्याज सहित ढाई लाख का जो चेक लगाया वह पुरानी इंदौर बैंक का था जिसका नाम अब बदल गया है।

लोकेंद्र का कहना है कि, सहारा समय बैंकक्रप्ट हो गई तो हमें क्या करना हमसे मुकेश पैसा ले गया था तो हमें मुकेश से पैसा चाहिए।

पहले अवैध रेत,गिट्टी का विज्ञापन लिखा था जो बाद में कलर कर मिटा दिया गया।

कांग्रेस के प्रदर्शन ने भाजपा की निंद उड़ाई, भाजपा के मंत्रियों के दौरे पर भी नहीं जुट रही भीड़

महंगाई , खाद ,राम मंदिर चन्दा चोरी से लेकर कर्ज माफी तक सरकार पर तीखे हमले

माही की गूंज ,पेटलावद। राकेश गेहलोत

बढ़ती महंगाई, खाद संकट, किसानों की विभिन्न समस्याओं एवं कृषि नीतियों के विरोध में रविवार को कांग्रेस और किसान कांग्रेस के नेतृत्व में पेटलावद में प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बामनिया रोड स्थित सुंदर गार्डन में आयोजित आमसभा से हुई। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने नगर के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली, जो तहसील कार्यालय पहुंची। यहां महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं के निराकरण की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। मुख्य अतिथि के रूप में आए मध्यप्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान ने आरोप लगाया कि प्रदेश और केंद्र सरकार किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार खाद की कमी और कृषि संबंधी समस्याओं को उठाती रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। उन्होंने दावा किया कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि मध्यप्रदेश में प्रतिदिन दो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं होने से खरीफ सीजन प्रभावित हो रहा है और ई-टोकन व्यवस्था के कारण किसानों को घंटों कतार में लगना पड़ रहा है।

राम मंदिर चोरी के मुद्दे से भाजपा पर निशाना

आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओर मप्र युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया ने अपने संबोधन में राम मंदिर से जुड़े कथित चोरी के मामले का उल्लेख करते हुए भाजपा पर तीखे राजनीतिक आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यदि बड़े उद्योगपतियों के करोड़ों रुपये के कर्ज माफ हो सकते हैं तो किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में किसानों के कर्ज माफ किए गए थे। उन्होंने नोटबंदी, खाद वितरण, केवाईसी व्यवस्था और महंगाई का भी उल्लेख किया तथा फोरलेन परियोजना में भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में असमानता का मुद्दा उठाते हुए इसे किसानों के साथ अन्याय बताया।

ई-टोकन खत्म कर पुरानी व्यवस्था लागू करने की मांग

थांदला विधायक वीरसिंह भूरिया, कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रकाश राका तथा जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष अकमाल मालू डामोर ने भी सभा को संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने किसानों को समय पर खाद, उचित मूल्य और कृषि संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। किसान कांग्रेस ने ई-टोकन व्यवस्था समाप्त कर पूर्व की व्यवस्था लागू करने की मांग करते हुए कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन पूरे जिले में और तेज किया जाएगा।सभा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने नगर के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली। रैली तहसील कार्यालय पहुंची, जहां महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया।

दिल्ली में धरना करते धरनारतों की धमकियों में अराजकता और जनता में फैलता झुठा विमर्श

माही की गूंज, झाबुआ।

भारत देश जहां का इतिहास ज्ञान, शिक्षा, और जागरुकता से भरा पड़ा है उस देश में शिक्षा और उसके माध्यमों की महत्वपूर्णता को समाप्त करते हुए विरोधियों द्वारा उसमें भ्रष्टाचार का बीज बोया। देखते ही देखते वर्षों में भारत में शिक्षा के माध्यमों में भ्रष्टाचार की जड़े फैलती गई जिसके कारणवश लोगों के अंदर अज्ञानता ने जन्म लिया और उनमें धैर्य की कमी ने मूल कारण को जानने या उसे समझने की क्षमता को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया। इसका लाभ विरोधियों ने उठाना शुरु कर भारत के विषय में यहां की परंपराओं पर झुठा विमर्श गढ़ते हुए उसे फैलाना शुरु किया।

किसी विषय को फैलाना हो तो उसे एक समस्या का रुप देकर उसमें मजबूरी और लाचारी को जोड़ दिया जाकर अन्याय का स्वरुप बनाकर प्रचार जोर-शोर से किया जाता है। सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक उस कुप्रचार को फैलाया जाता है। अब भारतीय जनता जिसमें धैर्य की कमी हो चूकी है उसमें झुठे विमर्श की गहराई में जाने की क्षमता होती नहीं फिर जो उसे दिखाया जाता है उसमें हालातो के मारो पर अन्याय होते देख नागरिक उसे ही सत्य मान लेते हैं किंतु उसकी सच्चाई जानते नहीं है न ही किसी प्रकार की खोज करते हैं फिर विडंबना यह भी है कि, जब प्रमाणिकता से न्युज या समाचार पत्रों द्वारा सच्चाई बताई जाती है तब वे या तो देखते-पढ़ते नहीं है या फिर बिना प्रमाण की बातों पर विश्वास करते हुए सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं।

ऐसा ही माहौल दिल्ली में धरने पर बैठे काकरोच जनता पार्टी ने बनाया और उनका साथ देने के लिए विपक्ष सड़क पर आ गया। विद्यार्थियों को लेकर सीजेपी जिस उद्देश्य से धरने पर बैठी थी उसके लिए सरकार से वार्ता होनी थी। फिर भी आंदोलन में हिंसा हो गई क्योंकि भीड़ बेलगाम थी, और विद्यार्थियों के साथ अराजक तत्व भी इसी आंदोलन में उपस्थित थे। जब धरना शुरु हुआ तब आंदोलनकारियों ने सरकार के विरोध में नारेबाजी की और साथ-साथ भारत के विरोध में भी, जो कि सरासर गलत है। बेलगाम आंदोलन में अराजक तत्वों ने मौका देखा और अपनी मनमानी का अवसर निकाल लिया। क्योंकि नेतृत्वहीन संसद मार्च की भीड़ को निर्देशित करने वाला कोई नहीं था। जब दिल्ली की सड़कों पर हंगामा हो रहा था तब काकरोच जनता पार्टी के दो नेता केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा से भेंट करने और ज्ञापन देने गए हुए थे। जिसमें चार घंटे का समय लगा और कुछ नेता भीड़ को संसद के करीब ले जाने में जी जान जुटा रहे थे बाकि एक नेता बर्गर से भूख मिटा रहा था। पुलिस और प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में घायल हुए दर्जनों वाहन क्षतिग्रस्त किए गए जिससे यह स्पष्ट होता है कि, हिंसा फैलाने वाले पहले से ही सोच समझ कर हिंसा की तैयारी से आए और शामिल हुए थे। जिन्होंने मीडिया पर भी हिंसा का प्रयोग किया और गोदी मीडिया से संबोधित कर आंदोलन से दूर किया। प्रदर्शनकारी विद्यार्थी ही थे जो इस तरह विरोध करते

हुए नारे लगाते आंदोलनकारी बने और सरकार का विरोध करते-करते सम्मान भी भूल गए।

संसद में मानसून सत्र चल रहा है जहां विपक्ष नीट पेपर लीक कांड के साथ अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ेगा। साथ ही साथ विपक्ष को नया मुद्दा सीजेपी के संसद मार्च में हुई हिंसा का मुद्दा भी मिल गया है। संसद सत्र में पहला दिन विपक्ष के हंगामें में बेकार ही गया और दूसरा दिन भी, हर बार हंगामें के बीच संसद सत्र को स्थगित किया जाता रहा है। इससे यही पता चलता है कि विपक्ष का कार्य संसद को नहीं चलने देना है, जबकि विपक्ष कानून या बनाए गए बिल की समिक्षा और उसमें मौजुद कमियां निकालने का होता है।

विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने साथियों के साथ अचानक सड़क की राजनीति करने के लिए प्रधानमंत्री आवास के पास धरने पर जा बैठे और नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने लगे। उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी पेपर लीक मामले को सड़क पर उछालने लगी। राहुल गांधी जिसका विरोध संसद में कर सकते हैं उसका विरोध करने के लिए उनको सड़क पर बैठने की क्या आवश्यकता पड़ गई। क्या राहुल गांधी काकरोच पार्टी के धरने से चिंतित हो उठे कि कथित राजनीति दल काकरोच पार्टी इतनी जल्दी चर्चा का विषय बन गई। जब दोनों का विरोध करने का विषय एक था तब राहुल गांधी क्यों अलग धरना लगाकर बैठे और उस समय जब कई विपक्षी दलों के नेता सीजेपी के मंच पर जाने लगे, अपना समर्थन देने लगे। तब कांग्रेस को उसी मुद्दे पर अलग से मौर्चा खोलना क्या यह दर्शाता है कि, सरकार का विरोध करने के मामले में कांग्रेस अपने आप को सबसे आगे खड़ी देखे। विरोध करने में विपक्षी दलों की आगे दिखने कि होड़ हास्यासपद है क्योंकि जिसक बहस सदन में की जा सकती है उसे सड़क पर करने से क्या लाभ।

जिस तरह से देश की जनता के सामने यह झुठा विमर्श फैलाया जा रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि विद्यार्थियों पर अन्याय हो रहा है, पुलिस द्वारा उन पर लाठिया चलाई जा रही है आसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। उससे अधिक सत्यता इसमें भी है कि भीड़ ने अराजकता का सहारा लिया और पुलिस पर पहले जमकर पत्थरबाजी की। हिंसा करने वालों ने पुलिस पर अमानक स्प्रे भी छीड़का। इस आंदोलनी हिंसा में पुलिस भीड़ का अनुमान नहीं लगा सकी और न ही नेतृत्वहीन हिंसा करने वाली भीड़ के इरादें का।

रिकेश बैरागी

बहरहाल, बीते सात वर्षों में यह तीसरी बार है जब देश की राजधानी आंदोलन से उपजी अराजकता की चपेट में आई है, और हर बार होता कुछ है और जनता को सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया और कुछ जाता है। भारतीय जनता को अपने अंदर के धैर्य को बनाकर उसे प्रबल करना होगा और हर उस बात की सच्चाई को समझना होगा। जब प्रधानमंत्री ने पेपर लीक करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कह दी है सरकार ने तत्काल कार्यवाही करते हुए सीबीआई जांच में 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हालांकि यह पहला मामला नहीं है जब किसी परिक्षा का पेपर लीक हुआ है, इससे पहले बहुत सी परिक्षाओं के पेपर लीक हो चुके है। सरकार को बीते वर्षों में हुए शिक्षा के माध्यम के इस भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए पेपर लीक करने वाले दोषियों को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा तभी भारत के भविष्य के भाव में प्रसन्नता आगेगी।

संपादकीय

कचरे का संकट

यह हमारी व्यवस्था की विडंबना ही है कि सड़कों व सार्वजनिक स्थलों में पसरा कचरा हटाना हमारी प्राथमिकता नहीं बनता। यह कचरा केवल दिखने में ही बुरा नहीं लगता बल्कि कई तरह के रोगों को जन्म देकर सार्वजनिक संकट का कारक भी बन सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हमारे समाज में सबसे महत्वपूर्ण सफाई का काम करने वाला वर्ग आर्थिक व सम्मान की दृष्टि से सबस ज्यादा उपेक्षित रहता है। कमोबेश पंजाब की सड़कों पर जमा कचरा यही संकट दर्शा रहा है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच घातक बीमारियां फैलने के खतरे को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की चेतावनी यह बताती है कि शहरी जीवन के लिये मूलभूत नागरिक सेवाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। खासकर मानसून के सीजन में यदि कचरा नहीं उठाया जाता तो स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है। बारिश में इस कचरे के बहने से नालियां जाम हो जाती हैं। वहीं पानी के स्रोत भी दूषित हो सकते हैं। साथ ही मच्छर,चूहे व कीट-पतंगे पनपने से बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में हाईकोर्ट का राज्यभर की नागरिक संस्थाओं से रिपोर्ट मांगना और सरकार की जवाबदेही तय करना वक्त की जरूरत भी है। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि नगर निकायों के अधिकारियों को जरूरी सेवाओं, विशेषकर लोगों की सेहत से सीधे जुड़ी सेवाओं के लिये आपातकालीन योजनाएं बनानी ही चाहिए। निस्संदेह, इस संकट को महज कानून व व्यवस्था के नजरिये से ही नहीं देखा जा सकता। निर्विवाद रूप से हमारे समाज में सफाई कर्मचारियों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन इस अहम कार्य को हम अपेक्षित मान्यता नहीं देते। यह विडंबना ही है कि सफाई कर्मचारी लंबे समय से नौकरी की असुरक्षा, स्थायी होने में लगने वाली देरी, मिलने वाला कम वेतन और काम करने की खराब स्थितियों की शिकायत करते रहते हैं। शोचनीय स्थिति यह है तंत्र सफाई कर्मचारियों की मांगों को तब तक नजरअंदाज करता है, जब तक वे अपनी मांगों के समर्थन में सड़कों में नहीं उतर जाते।

बहरहाल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सफाई कर्मचारियों को उनका वाजिब हक मिलना चाहिए। लेकिन हड़ताल व स्वास्थ्य सेवाओं का ठप होना न तो लोगों के हित में है और न ही सफाईकर्मियों के हक में। भारत में हर रोज 1.7 लाख टन से ज्यादा ठोस कचरा विभिन्न नगरपालिकाओं के अंतर्गत पैदा होता है। लेकिन तीव्र गति से बढ़ते शहरीकरण के चलते नागरिक सेवाओं पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में इस चुनौती के मुकाबले के लिये आधुनिक तकनीक के साथ प्रोफेशनल तरीके से ठोस कचरे का निस्तारण होना चाहिए। साथ ही जरूरी है कि पर्याप्त स्टाफ मिले, सफाई के आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराये जाएं। इसके अलावा इस क्षेत्र में निरंतर निवेश बढ़ाया जाए। हमारे नीति-नियंताओं को सोचना चाहिए कि आपातकाल के समय की गई कोई भी कार्रवाई लंबी अवधि की योजना का विकल्प नहीं बन सकती। ऐसे में सरकार के अधिकारियों को तुरंत सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत करनी चाहिए। उनकी जायज मांगों को एक तय समय सीमा में हल करने की दिशा में अविलंब काम करना चाहिए। इसके अलावा आपातकालीन इंतजामों के जरिये साफ-सफाई से जुड़ी सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहनी चाहिए। निस्संदेह, किसी भी तरह के विवाद के चलते आम लोगों की सेहत को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। यह भी विडंबना ही है कि जब तक सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा जमा होना शुरू नहीं होता, तब तक अक्सर शहरों की सफाई को हल्के में ले लिया जाता है। निश्चित रूप से हाल ही में पंजाब में पैदा हुए गतिरोध से हमें सबक लेना चाहिए। बल्कि इस चुनौती के बीच साफ-सफाई को एक जरूरी जन सेवा के तौर पर मान्यता देने का उपक्रम करना चाहिए। हमारा प्रयास हो कि हम शहरों की सफाई के लिये बेहतर नियोजन करें। इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सफाई के काम से जुड़े लोगों के कार्य का महत्व समझते हुए उन्हें पर्याप्त सम्मान दिया गया। नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते।

लोकतंत्र में सख्ती नहीं, उदार संवाद उपयोगी

वह मां अपनी तेरह-चौदह साल की बच्ची को लेकर राजधानी दिल्ली के 'प्रदर्शन-स्थल' जंतर-मंतर में आई थी। एक पत्रकार ने जिज्ञासा की तो उस मां ने कहा था, 'मैं अपनी बेटी को एक वास्तविकता से परिचित कराने लाई हूंकृकल उसे भी अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी।'

वह मां अकेली नहीं थी, जो अपनी संतान के बारे में इस तरह सोच रही थी। और वह बच्ची भी अकेली नहीं थी, जो अपने भीतर संघर्ष का एक जज्बा लेकर वहां पहुंची थी। उस दिन, जब सड़क से संसद तक पहुंचने की एक होड़-सी लगी थी युवाओं में, तो यह जज्बा अपने पूरे उफान पर था। हां, उस दिन वहां राजधानी दिल्ली के ही नहीं, देश के अलग-अलग हिस्सों से भी हजारों 'कॉकरोच' इकट्ठे हुए थे। ये 'कॉकरोच' पिछले लगभग एक माह से अधिक समय से अपने अधिकारों के लिए और अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए जंतर-मंतर पर बैठकर संघर्ष कर रहे थे। इस शांतिपूर्ण संघर्ष में कुछ ऐसे भी थे, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कारगर अस्त्रकृअनशन को अपना हथियार बनाया था। लद्दाख से आए सोनम वांगचुक का नेतृत्व मिला था इन युवाओं को।

एक मांग थी इन सबकीकृदेश की शिक्षा-व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाने वाली सरकार की नीतियों में बदलाव चाहते थे वे। देश का शिक्षामंत्री इन नीतियों का प्रतीक बना और देश के युवा यह मांग कर रहे थे कि वे स्थिति की जवाबदेही स्वीकार करें और अपने पद से इस्तीफा दें। पर देश की सरकार को यह स्वीकार नहीं था। ये युवा 6 जून से धरना दे रहे थे। हैरानी की बात यह है कि सरकार को न धरने की परवाह थी और न ही भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारियों की। शायद सरकार यह मानकर चल रही थी कि वे प्रदर्शनकारी थक जाएंगे और आंदोलन धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा। यदि यही सरकार की सोच थी, तो वह गलत थी।

सही क्या था, यह सरकार और देश ने संसद के मानसून अधिवेशन के पहले दिन देखा। हजारों की संख्या में देश के छात्र-युवा सरकार को यह दिखाने के लिए एकत्र हुए थे कि 'नीट' जैसी परीक्षाओं में हुए घोटालों से वे अपने भविष्य को अंधकारमय पा रहे हैं। देखा जाए तो

यह आंदोलन युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की लड़ाई है। सरकार ने इसे बहुत हल्के में लिया था। हो सकता है, कल सरकार की यह असंवेदनशीलता युवाओं को थका दे, पर यह सवाल अपनी जगह बना रहेगा कि जनतांत्रिक व्यवस्था में कोई सरकार अपने ही युवाओं के प्रति इस तरह का रवैया कैसे अपना सकती है?

हैरानी की बात यह भी है कि एक महीने से भी अधिक समय से चल रहे इस आंदोलन के प्रति हमारे मुख्यधारा के मीडिया ने भी लंबे समय तक उसे वह महत्व नहीं दिया, जो दिया जाना चाहिए था। हां, संसद तक पहुंचने की कूच वाले दिन हमारा मीडिया जरूर कुछ सक्रिय हुआ और तब देश को पता चला कि युवाओं का आक्रोश सचमुच उफान पर था।

संयोग की बात है कि जब राजधानी दिल्ली में देश के युवा अपनी व्यथा का प्रदर्शन कर रहे थे और न्याय की मांग कर रहे थे, तभी हमारे युवा वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की खोज की कहानी में अपना योगदान दर्ज करवाया। प्रधानमंत्री ने इन युवा प्रतिभाओं को बधाई देते हुए देश की युवा शक्ति की उपलब्धियों और संभावनाओं का बखान किया। प्रशंसा के पात्र हैं हमारे ये युवा वैज्ञानिक, पर उन युवाओं पर प्रधानमंत्री की निगाह क्यों नहीं गई, जो राजधानी में संसद के दरवाजे तक पहुंचकर अपनी पीड़ा उन तक पहुंचाना चाहते थे?

जब युवाओं की टोलियां संसद भवन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं, तो एक तरफ संसद भवन के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए और दूसरी ओर लाठियों तथा आंसू गैस के गोलों से उन्हें रोकने की कोशिश की गई। मीडिया की सहायता से सारे देश ने राजधानी की सड़कों पर छात्रों-युवाओं पर पुलिस की मार के दृश्य देखे। लाठीचार्ज में सैकड़ों छात्र-युवा घायल हो गए। पुलिस की ओर से इस हंगामे में घायल पुलिसकर्मियों की संख्या भी बताई गई। नहीं होना चाहिए था यहकृन छात्र घायल होने चाहिए थे, न पुलिस वाले। पर सवाल, जो पूछा जाना चाहिए, वह यह है कि यह स्थिति क्यों आई?

स्थिति के इस स्तर तक पहुंचने के बाद सरकार की ओर से युवाओं को बातचीत के लिए बुलाया गया। यह काम पहले क्यों नहीं हो सकता था? जनतंत्र में लाठी नहीं, संवाद हथियार होता है। हैरानी की बात है कि इस सारे हंगामे के दौरान सरकार को न सड़कों पर नारे लगाते युवा दिखे और न ही भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक और उनके युवा साथी।

हैरानी तो इस बात की भी है कि सरकार की ओर से यह कहना जरूरी समझा गया कि आंदोलनकारियों ने पहली बार बातचीत की पेशकश की है। क्या सरकार को इस बारे में पहल करने से किसी ने रोक रखा था? क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता था कि वह आंदोलन कर रहे युवाओं तक पहुंचकर उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश करती? क्या ऐसा करने से सरकार की इज्जत घट जाती? इस सारे प्रकरण में जो कुछ हुआ है, वह सरकार की असंवेदनशीलता को ही उजागर करता है। 'नीट' जैसी परीक्षाओं में हुई धांधली पहली बार हुई घटना नहीं है। अक्सर इस तरह के घोटाले सामने आते रहे हैं और अक्सर उनकी अनदेखी की जाती रही है। यह सही है कि इस बार 'नीट' की परीक्षा फिर से हो गई और माना जा सकता है कि सब ठीक हो गया है। पर यह तो स्वीकारना ही होगा कि हमारी शिक्षा-प्रणाली में कहीं न कहीं गड़बड़ी तो है, और इस गड़बड़ी के लिए किसी न किसी को अपना उत्तरदायित्व मानना ही होगा। बीस से अधिक छात्रों की आत्महत्या किसी भी एक मंत्री के इस्तीफे से कहीं अधिक गंभीर बात है। अब यदि 'कॉकरोच' कहे जाने वाले युवा शिक्षामंत्री के साथ-साथ प्रधानमंत्री के भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो उसका कारण भी स्थिति की गंभीरता को सरकार द्वारा न समझना ही होगा।

बहरहाल, छात्रों और युवाओं ने इस प्रकरण में अब तक सहनशीलता का ही परिचय दिया है। यह भी संभव है कि सरकार के अड़ियल

विश्वनाथ सचदेव

रुख के चलते निकट भविष्य में यह आंदोलन समाप्त भी हो जाए। पर युवा पीढ़ी में जो पीड़ा और आक्रोश दिखाई दिया है, वह किसी भी उत्तरदायी सरकार के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। इस बात को भी नहीं भुलाया जाना चाहिए कि कितनी भी कोशिश कर लें, पर 'कॉकरोच' एक ऐसी प्रजाति है, जो खत्म नहीं की जा सकी है। जब तक इसे 'परजीवी' कहकर दुत्कारा जाता रहेगा, समस्या का समाधान नहीं होगा। पहले समस्या को समझना जरूरी है, और यही कोशिश वे नहीं कर रहे, जिनके कंधों पर समस्याओं को समझने और उनका समाधान खोजने की जिम्मेदारी है। सवाल सिर्फ शिक्षा-प्रणाली में सुधार का नहीं, गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी जैसी उन समस्याओं को सुलझाने का भी है, जो आज के युवाओं को परेशान कर रही हैं।

जंतर-मंतर पर जो कुछ हुआ और संसद भवन तक पहुंचने की युवा आंदोलनकारियों की कोशिशें इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि देश की युवा पीढ़ी की पीड़ा और आक्रोश को समझने की ईमानदार कोशिश नहीं हो रही। बीस छात्रों की आत्महत्या किसी भी सरकार को हिलाने की ताकत रखती है। इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यह भी समझना जरूरी है कि हमारा आज का युवा सिर्फ हंगामा खड़ा करने में विश्वास नहीं करता, वह सूरत बदलने के लिए बेचैन है। इससे पहले कि उसका आक्रोश हताशा में बदल जाए, कुछ नहीं, बहुत कुछ सकारात्मक करने की आवश्यकता है। सरकार कब जागेगी?

'छात्रों की गूंज' और बदलता चुनावी विमर्श

उत्तराखंड की राजनीति पारंपरिक रूप से राष्ट्रवाद, सैन्य गौरव और धार्मिक अस्मिता के इर्द-गिर्द घूमती रही है। लेकिन हाल ही में देहरादून में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम ने राज्य और देश की मुख्यधारा की राजनीति को एक नया वैचारिक मोड़ दे दिया है। दो निरंतर कार्यकालों की सत्ता विरोधी लहर (एंटी-इंकम्बेंसी) से जूझ रही भाजपा के खिलाफ विपक्ष के पास मुद्दों का अंबार था। बेरोजगारी और महंगाई जैसे राष्ट्रव्यापी विषयों से लेकर बद्रीनाथ में दान चोरी के कथित विवाद और अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे बेहद संवेदनशील स्थानीय मुद्दों तक, कांग्रेस के तरकश में कई तीर थे।

पूरा राजनीतिक अमला और सत्ता पक्ष इस बात के लिए मुस्तैद था कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी देहरादून की धरती से इन सभी ज्वलंत मुद्दों पर तीखे तीर चलाएंगे। विशेष रूप से सैन्य बाहुल्य प्रदेश होने के नाते भाजपा को पूरा यकीन था कि राहुल गांधी 'अग्निवीर योजना' को लेकर सरकार को घेरेंगे। यही वजह थी कि राज्य सरकार ने रक्षात्मक रुख अपनाते हुए 17 जुलाई की शाम 5 बजे राहुल के कार्यक्रम से ठीक पहले आनन-फानन में अग्निवीर योजना को लेकर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कर डाला और सरकार में 'अग्निवीर प्रकोष्ठ' के गठन जैसी बड़ी घोषणाएं भी कर दीं। सरकार ने विपक्ष के सबसे बड़े हमले की धार को पहले ही कुंद करने की पूरी बिसात बिछा रखी थी।

लेकिन देहरादून के मंच पर राहुल गांधी ने न तो अग्निवीर का जिक्र किया और न ही अन्य राजनीतिक विवादों का। राहुल गांधी का पूरा ध्यान केवल और केवल एक मुद्दे पर केंद्रित रहाकृ'पेपर लीक और छात्रों के भविष्य पर सुनियोजित आघात।'

राहुल गांधी का यह रुख किसी राजनीतिक चूक का परिणाम नहीं, बल्कि एक गहरी और सुनियोजित दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस ने समझ लिया है कि राष्ट्रवाद और सैन्य मुद्दों पर भाजपा को उसकी पिच पर घेरना कई बार आत्मघाती साबित होता है। अग्निवीर पर बोलते ही बहस 'सेना के मनोबल' बनाम 'राजनीति' पर केंद्रित हो जाती, जिससे मूल मुद्दा भटक जाता।

उन्होंने राज्य के अन्य भावनात्मक मुद्दों को छुए बिना अपना पूरा फोकस देश और राज्य के युवाओं की सबसे दुखती रगकृ'पेपर लीक'कृपर रखा। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस की भावी रणनीति के केंद्र में अब 'युवा और छात्र' आ चुके हैं।

इससे पहले कोटा में छात्रों से संवाद के दौरान राहुल गांधी ने वर्तमान शिक्षा और परीक्षा प्रणाली को 'रिजेक्शन सिस्टम' करार दिया था। देहरादून का कार्यक्रम इसी वैचारिक विमर्श का अगला और अधिक परिपक्व पड़ाव था। यह जनसभा युवाओं की आकांक्षाओं, रोजगार, शिक्षा और अवसरों की उपलब्धता पर केंद्रित एक गंभीर संवाद था।

उत्तराखंड पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं, जैसे यूकेएसएसएससी और लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं, में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर राष्ट्रीय सुर्खियों में रहा है। हालांकि, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने त्वरित कदम उठाते हुए देश का सबसे कड़ा 'नकल विरोधी कानून' लागू किया और कई मामलों में गिरफ्तारियां भी कीं। सरकार ने इसे अपनी प्रशासनिक इच्छाशक्ति के रूप में पेश किया, लेकिन विपक्ष लगातार इसे इस रूप में प्रचारित करने में सफल रहा है कि व्यवस्था के भीतर बैठे लोग युवाओं के भविष्य के साथ 'अनंत अन्याय' कर रहे हैं।

राहुल गांधी इसी सामूहिक हताशा को एक बड़े राजनीतिक आंदोलन में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय राजनीति दशकों से जातिगत समीकरणों और धार्मिक ध्रुवीकरण के इर्द-गिर्द घूमती रही है। लेकिन 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम ने यह साफ संकेत दे दिया है कि भविष्य की राजनीति में जाति और धर्म के पारंपरिक औजारों के समानांतर रोजगार, शिक्षा और समान अवसर भी उतने ही प्रभावशाली चुनावी मुद्दे बनने जा रहे हैं।

अब सरकार के सामने असली चुनौती यह होगी कि वह केवल कड़े कानून बनाने तक सीमित न

जयसिंह रावत

रहे, बल्कि रोजगार और भर्ती व्यवस्था में सुधार के ऐसे ठोस और दृश्यमान परिणाम प्रस्तुत करे, जिससे युवाओं के बीच खोया हुआ भरोसा बहाल हो सके। यदि नियुक्तियां समय पर, बिना किसी धांधली के और पारदर्शी तरीके से होती हैं, तो विपक्ष के इस नैरेटिव की हवा अपने आप निकल जाएगी।

युवा मतदाता आज किसी भी राजनीतिक दल की किस्मत बनाने या बिगाड़ने में सबसे निर्णायक कारक बन चुके हैं। वे सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं, वे जागरूक हैं और अपनी समस्याओं के राजनीतिकरण को अच्छी तरह समझते हैं।

राहुल गांधी के देहरादून दौरे ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस अब लोकलुभावन और भावनात्मक बहसों के जाल में फंसने के बजाय सीधे उस मोर्चे पर लड़ना चाहती है, जहां सरकार सबसे ज्यादा संवेदनशील है।

मानवीय संवेदनाओं का धरातल पर बंटवारा

क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि जो जमीन हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली है, वह वास्तव में किसकी है? क्या वह केवल कागजों पर दर्ज हमारी एक निजी संपत्ति है जिसे हम जब चाहें, जैसे चाहें बेच दें? या फिर, उस मिट्टी के कण-कण पर हमारे पूरे परिवार, हमारे भाई-बहनों और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी कोई नैतिक और कानूनी हक है?

अक्सर गांवों, कस्बों और यहां तक कि शहरों में भी हमने देखा है कि जमीन के टुकड़े को लेकर घर के रिश्ते कैसे बिखर जाते हैं। किसी ने अपनी पुश्तैनी जमीन बिना परिवार से पूछे किसी बाहरी व्यक्ति को बेच दी, और बस इसी एक फैसले से सालों-साल चलने वाली कलह की नींव पड़ गई। भाई-भाई से अलग हो गया, संयुक्त परिवार टूट गए और जो जमीन कभी समृद्धि का प्रतीक थी, वह कड़वाहट और अदालती मुकदमों की जड़ बन गई।

लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 'महिंदर और अन्य बनाम पूरन सिंह' (14 जुलाई, 2026) मामले में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जो भारत के हर उस परिवार के लिए एक 'सुरक्षा कवच' बन गया है, जिसके पास खेती की जमीन है। यह फैसला केवल कानूनी किताबों की कोई सूखी शब्दावली नहीं है, बल्कि यह उन परिवारों की सामाजिक एकता को बचाने की कोशिश है, जिनकी जड़ें आज भी अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। यह कानूनी संघर्ष निचली अदालतों से शुरू हुआ था। विवाद का मुख्य मुद्दा बहुत सरल लेकिन गहरा था रू क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 22, खेती की जमीन पर भी लागू होती है? निचली अदालतों में एक लंबा तर्क चला कि खेती की जमीन आम संपत्तियों से अलग होती है। कुछ लोगों का कहना था कि यह आजीविका का साधन है, इसलिए इस पर मालिक का पूरा नियंत्रण होना चाहिए और उत्तराधिकार के सामान्य कानून इस पर लागू नहीं होने चाहिए।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम शंकाओं को एक झटके में खत्म कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून की नजर में पुश्तैनी संपत्ति का स्वरूप नहीं बदलता। चाहे वह रहने का घर हो या खेती का खेत, यदि वह विरासत में मिली है, तो उसके प्रति कानूनी दायित्व समान हैं। कोर्ट ने यह संदेश दिया कि जमीन की प्रकृति बदल सकती है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी का स्वरूप नहीं।

सरल शब्दों में कहें तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 का मतलब हैदृ 'परिवार का पहला हक'। यह धारा कहती है कि यदि कोई वारिस विरासत में मिली संपत्ति का अपना हिस्सा बेचना चाहता है, तो वह सीधे किसी अनजान व्यक्ति या बाहरी खरीदार के पास नहीं जा सकता। इसे 'प्रिएम्पशन का अधिकार' कहा जाता है, जिसके अंतर्गत बाहरी व्यक्ति को जमीन बेचने की स्वतंत्रता केवल तभी मिलती है जब परिवार का कोई भी सदस्य उसे खरीदने में रुचि न रखे या असमर्थ हो। यह कानूनी प्रावधान परिवार की पुश्तैनी विरासत को बाहरी हस्तक्षेप से बचाकर उसकी सामाजिक एकता और सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम है।

यूरोप के जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में खेती की जमीन को 'अविभाज्य इकाई' मानकर कड़े कानूनों के जरिए उसे परिवार के भीतर ही सुरक्षित रखा जाता है, ताकि पुश्तैनी परंपराएं बनी रहें। इसके विपरीत, अमेरिका में व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है और जमीन बेचने की पूरी आजादी है, लेकिन वहां भी संपन्न परिवार अपनी विरासत को बाहरी हस्तक्षेप से बचाने के लिए 'फैमिली ट्रस्ट' और 'कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स' जैसी कानूनी व्यवस्थाओं का समझदारी से उपयोग करते हैं।

भारत का कानून इन दोनों के बीच का एक संतुलन है। हम व्यक्ति की आजादी का भी सम्मान करते हैं, लेकिन परिवार और समाज की एकता को भी बहुत महत्व देते हैं। यह भारतीय कानून की खूबी है कि वह हमें व्यक्तिगत अधिकार तो देता है, लेकिन साथ ही हमें यह याद दिलाता है कि हम एक सामाजिक इकाई का हिस्सा हैं। यह हमें दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले एक अधिक मानवीय चेहरा प्रदान करता है, जो रिश्तों को सिर्फ पैसे से ऊपर रखकर देखता है।

इस तरह, यह कानून न केवल विवादों को जन्म लेने से रोकता है, बल्कि परिवार के भीतर आपसी संवाद और रिश्तों की मजबूती को भी अनिवार्य बनाता है। निरूसंदेह, जमीन का संरक्षण केवल संपत्ति का अधिकार नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को उनकी जड़ों से जोड़े रखने का एक पुनीत कर्तव्य है। यह कानून हमें याद दिलाता है कि कानून की असली सार्थकता तब सिद्ध होती है, जब वह न्याय प्रदान करने के साथ-साथ हमारी सामाजिक जड़ों को भी सींचता रहे। आज के दौर में जब संयुक्त परिवार सिमट रहे हैं और भौतिकवाद हावी हो रहा है, यह फैसला एक संजीवनी का कार्य करता है। यह कानून हमें याद दिलाता है कि परिवार कोई कानूनी अनुबंध नहीं, बल्कि विश्वास और साझा दायित्वों का समूह है। संपत्ति के बंटवारे के समय श्न्यायश् केवल कागजी नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के धरातल पर भी होना चाहिए।

डॉ. सुधीर कुमार

अगली बार जब आप अपने पुश्तैनी खेतों की मेड़ पर खड़े हों, तो याद रखिएगा कि वह जमीन मात्र मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार का सांझा इतिहास है। यदि अब आपसे कोई कहे कि 'मेरी जमीन, मैं किसी को भी बेचूं,' तो उन्हें धारा 22 की यह सरल सीख अवश्य याद दिलाइए दृ 'कानून के अनुसार, पहला हक घर का, बाद में बाहर काय पहले परिवार को पूछिए, फिर बाहर देखिये!' यह कानून न केवल जमीन को सुरक्षित रखेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के बीच रिश्तों की डोर को भी और मजबूत करेगा।

जल जीवन मिशन के 155 पाइप चोरी, दो ठेकेदार गिरफ्तार

माही की गूंज, रतलाम।

जिले में जल जीवन मिशन परियोजना के 155 लोहे के पाइप चोरी करने के मामले में पुलिस ने दो ठेकेदारों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी राजस्थान के अलवर जिले के निवासी हैं और रावटी क्षेत्र में एक अन्य पाइपलाइन परियोजना पर कार्य कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर आगे की कार्रवाई शुरू की है।

बिलपांक थाना क्षेत्र में मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, हैदराबाद के प्रबंधक प्रसाद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि कंपनी जल जीवन मिशन के अंतर्गत माही जल समूह प्रदाय योजना पर कार्य कर रही है। ईंटावा खुर्द और शिवपुर के बीच पाइपलाइन बिछाने के लिए सुराना-शिवपुर मार्ग पर 300 मिलीमीटर व्यास के 809 लोहे के पाइप रखे गए थे।

वर्षा के कारण खुदाई कार्य बंद था। जब कंपनी का दल पाइपों का निरीक्षण करने पहुंचा तो 809 में से 155 पाइप कम पाए गए। चोरी हुए पाइपों की कीमत 15 लाख रुपये से अधिक बताई गई है।

कंपनी द्वारा घटना के कुछ दिन बाद शिकायत दर्ज कराने पर पुलिस ने जांच शुरू की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की। फुटेज में देर रात कुछ लोग हाइड्रा मशीन की सहायता से पाइप दो मालवाहक ट्रकों में भरते हुए दिखाई दिए

जांच के दौरान पुलिस हाइड्रा मशीन तक पहुंची, जो सालाखेड़ी स्थित एक निजी वाहन पार्किंग में मिली। पार्किंग की रसीद के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची और जांच के सिलसिले में राजस्थान गई।

पुलिस जांच में सामने आया कि वसीम मेव (24) रावटी क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने का ठेका लेकर कार्य कर रहा था। कार्य बंद होने पर उसने अलवर लौटते समय पाइप चोरी की योजना बनाई। इस वारदात में उसका मामा शाहरुख मेव (30) भी शामिल था। दोनों आरोपी अलवर जिले के निवासी हैं।

बिलपांक थाना प्रभारी अयूब खान ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रतलाम लाया गया है।

पूछताछ में मालवाहक ट्रकों, हाइड्रा मशीन के चालकों तथा पाइप बेचने वाले एक एजेंट के संबंध में जानकारी मिली है। इनकी तलाश के लिए पुलिस दल राजस्थान भेजा गया है। चोरी में प्रयुक्त ट्रकों की भी तलाश की जा रही है। पुलिस आरोपियों से आगे पूछताछ कर मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

शराब दुकान में तोड़फोड़, कर्मचारी से मारपीट

माही की गूंज, रतलाम।

जिले के बिलपांक थाना क्षेत्र के ग्राम पलाश में शराब दुकान पर फ्री में शराब नहीं देने पर तीन लोगों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दी। आरोपियों ने दुकान के भीतर तोड़फोड़ कर सामान भी बिखेर दिया। घटना का दृश्य दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार घटना मंगलवार शाम करीब सात बजे की है। गांव के तीन व्यक्ति शराब दुकान पर पहुंचे और क्षेत्र में दुकान संचालित करने के नाम पर हर माह राशि देने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने निरूशुल्क शराब देने का दबाव बनाया। कर्मचारियों द्वारा इनकार किए जाने पर आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी और दुकान में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस ने दुकान के कर्मचारी टिंकल सिंह (31) पिता दिनेश सिंह, निवासी ग्राम कटघरा थाना सिकंदपुर, जिला बलिया (उत्तर प्रदेश), हाल निवासी ग्राम पलाश की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और शिकायत के आधार पर शेरसिंह निवासी ग्राम पलाश, बंशी पिता नाथु निवासी ग्राम आंबाछायन तथा सोनु पिता मोहन निनामा निवासी ग्राम भोलासा के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। बताया गया है कि आरोपी शेरसिंह का खेत और मकान शराब दुकान के समीप स्थित है।

बिलपांक थाना प्रभारी अयूब खान ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ मारपीट, अवैध वसूली, जान से मारने की धमकी तथा अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

माही की गूंज, मंदसौर।

दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और विपक्षी नेताओं के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने शहर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौराहा स्थित कांग्रेस कार्यालय से सिटी कोतवाली तक पैदल मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से रखने वाले छात्रों पर बल प्रयोग किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे को लेकर धरना दे रहे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी सहित अन्य विपक्षी नेताओं और सांसदों के साथ भी अनुचित व्यवहार किया गया।

ज्ञापन में कहा गया कि छात्र देश का भविष्य हैं और उनकी समस्याओं को संवाद के माध्यम से सुना जाना चाहिए। लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना आवश्यक है।

कांग्रेस ने राष्ट्रपति से मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की। साथ ही नीट प्रश्नपत्र लीक प्रकरण के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी उठाई गई।

प्रदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इष्टा भाचावत, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख, कांग्रेस नेता दीपक सिंह गुर्जर, सोमिल नाहटा, मनजीत सिंह मनी, तरुण खींची, माजिद चौधरी सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

नाबालिग छात्र हत्या प्रकरण की सीआईडी कर रही जांच

माही की गूंज, शुजालपुर।

जिले के नांदनी गांव में 10 वर्षीय छात्र की हत्या के मामले की जांच अब सीआईडी द्वारा की जा रही है। जांच के दौरान सामने आए नए साक्ष्यों के आधार पर मामले में पॉक्सो अधिनियम सहित अन्य धाराएं भी जोड़ी गई हैं। पुलिस और सीआईडी दोनों स्तर पर मामले की गहन जांच जारी है।

सीआईडी भोपाल के सहायक पुलिस महानिरीक्षक धनंजय शाह ने बताया कि मृतक और आरोपी दोनों नाबालिग हैं। घटनास्थल से प्राप्त भौतिक साक्ष्यों का परीक्षण किया जा रहा है। जांच के दौरान छात्र के साथ यौन अपराध से संबंधित पहलुओं के संकेत मिलने पर मामले में संबंधित धाराओं का समावेश किया गया है।

इस प्रकरण में पहले पुलिस ने एक 17 वर्षीय नाबालिग को अभिरक्षा में लिया था। प्रारंभिक जांच को लेकर मृतक के परिजनों ने कई सवाल उठाए थे। परिजनों का कहना था कि जिस किशोर को आरोपी बताया गया, वह छात्र के लापता होने के बाद उसकी तलाश में भी शामिल था। उन्होंने मामले में अन्य लोगों की संभावित संलिप्तता की आशंका भी जताई है।

परिजनों और ग्रामीणों के असंतोष के बाद क्षेत्र में प्रदर्शन किया गया था तथा मामले की सीआईडी जांच की मांग उठाई गई थी। इसके बाद राज्य शासन ने प्रकरण की जांच सीआईडी को सौंप दी।

सीआईडी दल ने जांच अपने हाथ में लेने के बाद घटनास्थल का दो बार निरीक्षण किया है। दल ने स्थानीय पुलिस और न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की टीम से भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। जांच दल घटनाक्रम, साक्ष्यों और प्रारंभिक विवेचना से संबंधित सभी पहलुओं का परीक्षण कर रहा है।

जांच के दौरान आरोपी से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों की भी पड़ताल की जा रही है। इसके लिए आवश्यक होने पर न्यायालयिक वैज्ञानिक सहायता ली जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच की जा रही है तथा जांच पूरी होने के बाद ही अंतिम स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

कालापीपल थाना प्रभारी रवि भंडारी ने बताया कि प्रारंभिक साक्ष्य मिलने पर संबंधित धाराएं पहले ही जोड़ दी गई थीं। पुलिस जांच एजेंसी के साथ समन्वय कर मामले की विवेचना में सहयोग कर रही है।

स्कूल के लिए निकले शिक्षक का शव मिला रेलवे ट्रैक पर

माही की गूंज, शाजापुर।

जिले के मक्सी थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर मिले शिक्षक के शव के मामले में पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज किया है। जांच के दौरान मृतक के मोबाइल फोन से एक संदेश मिला, जिसमें उसने अपने बारे में अफवाहें फैलाए जाने का उल्लेख करते हुए आत्महत्या के लिए एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया था।

मृतक की पहचान ग्राम सिरोलिया निवासी सतीश जोशी (38) के रूप में हुई है। वह एक निजी विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। पुलिस ने इस मामले में ग्राम सिरोलिया निवासी दीपक उर्फ गोलू पाटीदार को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

पुलिस के अनुसार सतीश जोशी घटना वाले दिन सुबह विद्यालय जाने के लिए घर से निकले थे। शाम को सिरोलिया रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक पर उनका शव मिलने की सूचना परिजनों को मिली थी।

मर्ग जांच के दौरान पुलिस ने मृतक के भाई दिनदयाल जोशी सहित अन्य लोगों के बयान दर्ज किए। जांच में मृतक के मोबाइल फोन से प्राप्त एक व्हाट्सऐप संदेश को भी शामिल किया गया। पुलिस के अनुसार संदेश में सतीश जोशी ने दीपक उर्फ कालू पाटीदार पर पिछले करीब दो माह से परेशान करने और गलत अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया था। उन्होंने आत्महत्या के लिए उसे जिम्मेदार ठहराते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी।

मर्ग जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मक्सी पुलिस ने ग्राम सिरोलिया निवासी दीपक उर्फ कालू पाटीदार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

बाइक के इंजन में घुसा सांप, दो घंटे तक निकालने का चला प्रयास

माही की गूंज, सेंधवा। नगर के पुराने एबी रोड क्षेत्र में बुधवार दोपहर एक बाइक के इंजन में सांप घुस जाने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सांप को बाहर निकालने के लिए करीब दो घंटे तक प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। घटना के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए।

जानकारी के अनुसार एक युवक अपनी बाइक चालू करने वाला था। इसी दौरान पास खड़े एक व्यक्ति ने उसे सावधान करते हुए बताया कि बाइक में सांप घुस गया है। सूचना मिलते ही युवक तुरंत बाइक से उतर गया और अपने साथियों के साथ सांप की तलाश शुरू कर दी।

कुछ देर बाद इंजन के पास से सांप का सिर दिखाई दिया। यह दृश्य देखते ही आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और सांप को बाहर निकालने के प्रयास शुरू किए गए। करीब दो घंटे तक विभिन्न तरीकों से सांप को बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वह इंजन के भीतर ही छिपा रहा। अंततः युवक ने बाइक को सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर दिया और सांप के स्वयं बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। घटना के दौरान पुराने एबी रोड से गुजरने वाले राहगीर भी रुककर पूरा घटनाक्रम देखते रहे। काफी देर तक यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही।

महिला से छेड़छाड़ के मामले में दो आरोपियों को सजा

माही की गूंज, शाजापुर।

जिले के जाईहेड़ा गांव में महिला से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने आरोपी मुलायम और शुभम को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रतीक श्रीवास्तव के अनुसार घटना 21 फरवरी 2022 की है। पीड़िता अपनी बहन के साथ खेत से लौट रही थी। रास्ते में खड़े वाहन को हटाने की बात को लेकर आरोपियों ने विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि इस दौरान दोनों आरोपियों ने महिला का हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ की तथा बीच-बचाव करने पहुंची उसकी बुआ को जान से मारने की धमकी दी।

घटना के बाद पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पूरी करने के बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी माना। मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ममता पाराशर ने पैरवी की।

न्यायालय ने दोनों दोषियों को धारा 354 के तहत दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपये अर्थदंड, धारा 354-क के तहत एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 509 के तहत छह-छह माह के सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

चादर का फंदा लगाकर युक ने की आत्महत्या

माही की गूंज, रतलाम।

शहर के काटजू नगर क्षेत्र में एक 35 वर्षीय युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बुधवार को घर से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा खोलकर देखा तो युवक दूसरे कमरे में चादर के फंदे से पंखे पर लटका हुआ मिला।

प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई है कि युवक ने करीब 24 घंटे पहले आत्महत्या की थी। पुलिस को घटनास्थल से कोई आत्महत्या पत्र नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि युवक की दो माह पहले दूसरी शादी हुई थी, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी।

मृतक की पहचान सुरेश उर्फ लखन (35) पिता दर्शन चौहान, निवासी काटजू नगर के रूप में हुई है। वह एक बहुमंजिला भवन की पहली मंजिल पर अकेला रहता था। बुधवार दोपहर भवन में रहने वाले लोगों को उसके घर से दुर्गंध आने लगी। पड़ोसियों के अनुसार सुरेश मंगलवार दोपहर से दिखाई नहीं दिया था। संदेह होने पर औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस को सूचना दी गई।

सूचना मिलने पर थाना प्रभारी गायत्री सोनी, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) के अधिकारी डॉ. अतुल मित्तल तथा पुलिस दल मौके पर पहुंचा। पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को फंदे से उतारकर शव परीक्षण के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। घर की तलाशी के दौरान कोई आत्महत्या पत्र बरामद नहीं हुआ।

पुलिस जांच में सामने आया कि सुरेश का विवाह 30 अप्रैल 2026 को नागदा निवासी कविता उर्फ थापू के साथ रतलाम स्थित गढ़कैलाश महादेव मंदिर में हुआ था। महिला का यह दूसरा विवाह था। उसके पहले विवाह से एक 15 वर्षीय बेटी और 10 वर्षीय पुत्र है। जानकारी के अनुसार विवाह के लगभग 10 दिन बाद ही पत्नी घर छोड़कर चली गई थी और वापस नहीं लौटी। बाद में जून 2026 में दोनों का तलाक हो गया था।

सुरेश कबाड़ सामग्री से जुड़े एक मालवाहक वाहन का चालक था। उसके पिता का लगभग 10 वर्ष पहले तथा माता पुष्पाबाई का पांच वर्ष पहले निधन हो चुका था। घटना की सूचना मिलने पर उसकी मौसी की बेटी सपना कायस्थ जावरा से रतलाम पहुंचीं और पुलिस को परिवार तथा विवाह संबंधी जानकारी दी।

न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के अधिकारी डॉ. अतुल मित्तल ने बताया कि शव की स्थिति और दुर्गंध के आधार पर अनुमान है कि युवक ने लगभग 24 घंटे पहले फांसी लगाई होगी। मृत्यु का सही समय और कारण शव परीक्षण रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा।

थाना प्रभारी गायत्री सोनी ने बताया कि मर्ग कायम कर सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है।

ज्योतिर्लिंग मंदिर में पंडितों के प्रवेश पर रोक से विवाद

माही की गूंज, ओंकारेश्वर।

भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में बुधवार सुबह 9 बजे के बाद नियमित पूजन-अर्चन करने वाले पंडितों के प्रवेश पर रोक लगाए जाने से विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। पंडितों ने मंदिर परिसर में इस व्यवस्था का विरोध करते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

पंडितों का आरोप है कि मंदिर के टी-पॉइंट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिनके अनुसार सुबह 9 बजे के बाद किसी भी पंडित को मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

पंडित राधे तिवारी तथा नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पंडित नवल किशोर शर्मा ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े प्रभारी तिलोक त्यागी द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर यह व्यवस्था लागू की गई है। सुरक्षा कर्मियों को आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। पंडितों का कहना है कि यह व्यवस्था अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुनासा पंकज वर्मा के निर्देश पर लागू की गई है।

घटना के बाद पंडितों ने प्रशासन के समक्ष अपनी मांगें रखते हुए अधिकृत पंडितों को मंदिर में निर्बाध प्रवेश देने, यजमानों के साथ जलाभिषेक की अनुमति बहाल करने तथा अभिषेक कक्ष में श्रद्धालुओं का विधिवत पूजन कराने की व्यवस्था पुनः शुरू करने की मांग की।

पंडितों ने पूरे मामले की जानकारी दूरभाष पर खंडवा कलेक्टर ऋषव गुप्ता को दी। कलेक्टर ने समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है।

पंडितों का कहना है कि यदि उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा तो श्रद्धालुओं के पारंपरिक पूजन-अर्चन की व्यवस्था प्रभावित होगी। वहीं, स्थानीय लोगों ने भी इसे पंडितों की आजीविका से जुड़ा विषय बताते हुए प्रशासन से स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है।

जानकारी के अनुसार मंगलवार को पंडित दिनेश शर्मा कुछ श्रद्धालुओं के साथ मंदिर दर्शन के लिए गए थे। सभी श्रद्धालुओं के पास ऑनलाइन दर्शन टिकट थे। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं के साथ मंदिर में प्रवेश करते समय उनकी गतिविधियां निगरानी कैमरों में दिखाई दीं, जिसके बाद प्रशासन स्तर पर मामले को लेकर चर्चा हुई।

इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों द्वारा मंदिर के टी-पॉइंट से पंडितों के प्रवेश पर रोक संबंधी निर्देश जारी किए गए। बुधवार सुबह से इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया, जिसके चलते कई पंडितों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया।

फिलहाल इस मामले में प्रशासन अथवा मंदिर ट्रस्ट की ओर से कोई आधिकारिक लिखित आदेश सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब सभी की नजरें प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट की आगामी बैठक तथा निर्णय पर टिकी हुई हैं।

पेपर लीक मामले में लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

माही की गूंज, खरगोन।

पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने बुधवार को लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया तथा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।

प्रदर्शन की शुरुआत सुबह 11 बजे नगर के श्रीकृष्ण टॉकीज चौराहे पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाईक के नेतृत्व में हुई। कार्यकर्ताओं ने करीब दो घंटे तक धरना दिया। इसके बाद दोपहर में शहर के विभिन्न मार्गों से रैली निकाली गई। रैली नारेबाजी करते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय परिसर पहुंची, जहां राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी सत्येंद्र बैरवा को सौंपा गया। प्रदर्शन में कादर बैग, नीमा गौर, पार्षद अरुणा उपाध्याय, असलम खान, निलेश सागोरे, अमित भालसे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाईक ने कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर पेपर लीक मामले को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना से देश की छवि प्रभावित हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार से मामले में उचित कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो कांग्रेस का चरणबद्ध आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।

मौसी की बेटी पर शादी के गहने और नकदी चोरी करने का आरोप

माही की गूंज, खंडवा।

मूंदी पुलिस ने शादी के लिए रखे गए गहनों और नकदी की चोरी के मामले का खुलासा करते हुए नागपुर (महाराष्ट्र) से एक युवती सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1.15 लाख रुपए नकद, लगभग 2.50 लाख रुपए मूल्य के सोने के आभूषण तथा वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की है। बरामद संपत्ति का कुल मूल्य लगभग 3.65 लाख रुपए बताया गया है।

पुलिस के अनुसार तालाब मोहल्ला, मूंदी निवासी ऋषभ पिता विनोद राठौर ने 17 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि उनकी मौसी की बेटी अम्बिका उर्फखुशी शादी के लिए रखे गए सोने के आभूषण और 1.80 लाख रुपए नकद लेकर चली गई है। शिकायत के आधार पर मूंदी थाने में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई।

जांच के दौरान पुलिस ने विभिन्न संभावित ठिकानों पर दबिश दी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर पुलिस दल नागपुर पहुंचा और कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों में अम्बिका उर्फ खुशी (18 वर्ष), रमजान शेख (24 वर्ष) और मुकेश उर्फ भैरव (22 वर्ष) शामिल हैं। तीनों पंधाना थाना क्षेत्र के बोरगांव बुजुर्ग के निवासी बताए गए हैं।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 2.50 लाख रुपए मूल्य के सोने के आभूषण, 1.15 लाख रुपए नकद तथा वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की है। बरामद माल की कुल कीमत लगभग 3.65 लाख रुपए आंकी गई है।

पूछताछ और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय से जेल वारंट जारी होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार मामले के खुलासे में थाना प्रभारी राजेंद्र नरवरिया, निरीक्षक उमेश लाखरे, बोरगांव चौकी प्रभारी अविनाश भोपले, सहायक उपनिरीक्षक फिरोज खान तथा आरक्षक नरेंद्र यादव और दिनेश सिसोदे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

छात्रों ने सांसद आवास के बाहर किया प्रदर्शन

माही की गूंज, बड़वानी।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में बुधवार को खरगोन-बड़वानी लोकसभा क्षेत्र में विरोध-प्रदर्शन तेज हो गया। सेंधवा और बड़वानी से पहुंचे छात्रों ने सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के आवास के बाहर धरना देकर विरोध दर्ज कराया। हल्की बारिश के बावजूद छात्र लंबे समय तक मौके पर डटे रहे।

प्रदर्शन की शुरुआत में कुछ ही छात्र पहुंचे थे। सूचना मिलने पर शहर कोतवाली थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन मौके पर पहुंचे। बाद में सूचना विभिन्न माध्यमों से फैलने पर छात्रों की संख्या बढ़ गई। छात्रों ने हाथों में पोस्टर, तख्तियां और संविधान की प्रतियां लेकर केंद्र सरकार तथा सांसद के खिलाफ नारेबाजी की।

धरने का नेतृत्व कर रहे सेंधवा निवासी छात्र अमरदीप चौहान ने कहा कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग किया जाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि युवाओं की समस्याओं को सुनने के बजाय उन पर कार्रवाई करना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने इस मामले पर जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए।

प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि इस घटना को लेकर क्षेत्र के युवाओं में नाराजगी है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की।

छात्रों ने सरकार से शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेने, पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शन के बाद सांसद आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में आंदोलन आगे भी जारी रखा जाएगा।

गुरु पूर्णिमा से पहले तैयार होगा इंदौर रोड फ्लाईओवर

माही की गूंज, खरगोन।

खलघाट-पाल 347सी राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन इंदौर रोड फ्लाईओवर का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। आगामी गुरु पूर्णिमा महोत्सव को देखते हुए निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है। फ्लाईओवर के संपर्क मार्ग और भूमिगत मार्ग पर डामरीकरण का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। प्रशासन ने 25 जुलाई तक निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

29 जुलाई को इंद्र टेकड़ी स्थित पूर्णानंद बाबा की समाधि पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव आयोजित होगा। महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए निर्माण कार्य समय पर पूरा कराने में जुटा है।

मंदिर समिति ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने निर्माण कार्य में हो रही देरी को लेकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सत्येंद्र बैरवा से मुलाकात कर फ्लाईओवर का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने की मांग की थी। इसके बाद प्रशासन ने निर्माण एजेंसी के अधिकारियों के साथ बैठक कर 25 जुलाई तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

प्रशासन की सख्ती के बाद निर्माण एजेंसी ने मौके पर मशीनों और श्रमिकों की संख्या बढ़ा दी है। संपर्क मार्ग, भूमिगत मार्ग तथा अन्य शेष हिस्सों पर तेजी से कार्य किया जा रहा है।

फ्लाईओवर का अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वर्तमान में संपर्क मार्ग और भूमिगत मार्ग पर डामरीकरण का कार्य अंतिम चरण में है। हालांकि, यातायात संकेतक लगाने तथा कुछ सुरक्षा संबंधी कार्य अभी शेष हैं, जिन्हें निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण विभाग के उप संभागीय अधिकारी अविनाश सोनी ने बताया कि शेष निर्माण कार्य और यातायात संकेतक लगाने का कार्य तय समय सीमा में पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव से पूर्व फ्लाईओवर को पूरी तरह तैयार करने के लिए निर्माण एजेंसी लगातार कार्य कर रही है।

फ्लाईओवर का निर्माण पूर्ण होने के बाद गुरु पूर्णिमा महोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं को यातायात अवरोध और जाम की समस्या से राहत मिलेगी। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन अधिक सुरक्षित और सुगम हो सकेगा।

इस छात्र आंदोलन के दीर्घकालीन होने का निहितार्थ

जब 'कॉकरोच जनता पार्टी' आंदोलनकारियों ने संसद की ओर कूच किया, तो सत्ता के नशे में चूर सरकार ने - जो किसी भी किस्म का विरोध सहना तो एक तरफ, असहमति तक बर्दाश्त नहीं करती-अपने अहंकार में उन युवाओं पर हाथ उठवाया जिन्होंने सिर्फ उपवास किया था, धरना दिया और अपनी बात रखी थी। आज दोपहर हुई धक्का-मुक्की, लाठीचार्ज, खून बहना और आंसू गैस के दृश्य भुलाना मुश्किल होगा। यह उस घटनाक्रम का नतीजा था जो शनिवार सुबह, 18 जुलाई को शुरू हुआ था, जब इस आंदोलन से जुड़े सबसे जाने-माने चेहरों में से एक, सोनम वांगचुक को पुलिस ने बेहद कमजोर व बेबुनियाद कारणों के आधार पर वहां से हटाया। शनिवार और रविवार को, उनकी गैर-मौजूदगी में भी जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन अनवरत जारी रहा।

तथापि, अगर इस हिंसा के पीछे मकसद आंदोलन को तोड़ना था, तो पिछले कुछ दिनों ने इसके उलट साबित कर दिखाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आंदोलन किसने शुरू किया, अब इसका नेतृत्व कौन कर रहा, या वहां मौजूद सभी हर मुद्दे पर सहमत हैं या नहीं। मायने यह रखता है कि युवाओं ने इतनी बड़ी संख्या में आकर सामूहिक रोष जताया। यह किसी एक चेहरे, नाम या पार्टी से कहीं बड़ी बात है। अपनेआप में लोकतंत्र की जबरदस्त लहर है। मैंने अपने सामने यह होते देखा, पहले शनिवार को और फिर आज। मैं 18 जुलाई को जंतर-मंतर पर उपवासरत छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने गया था। पहले इसलिए नहीं जा सका कि दिल्ली से बाहर, अपने गृह राज्य में कुछ जरूरी और न टाली जा सकने वाली प्रतिबद्धताओं में व्यस्त था। जब उस सुबह सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने की खबर मिली, तो कुछ पल के लिए सोचा कि क्या ऐसे समय में विरोध स्थल पर जाना उचित होगा। मैंने सोचा कि अवश्य ही माहौल मायूसी भरा होगा। फिर खुद को याद दिलाया कि एकजुटता दिखाने का असली औचित्य तो तभी है, जब आंदोलन को डराने या हौसला तोड़ने की कोशिश की जा रही हो।

जंतर-मंतर पर मैंने जो देखा, वह मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग था। मायूसी और थकावट के बजाय, दृढ़ संकल्प और हिम्मत व्याप्त देखी। माहौल आशा, नैतिक विश्वास और सामूहिक मकसद के असाधारण भाव से लबरेज था। ये सब युवा कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले इकट्ठा थे, ऐसा नाम जो विद्रोह दर्शाता है। जब तंत्र के सबसे ऊंचे ओहदों में से एक की ओर से देश के बेरोजगार युवाओं की तुलना के लिए कॉकरोच जैसे अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया गया, तो युवाओं ने इस ताने को बतौर पहचान अपना लिया।

सामाजिक आंदोलनों के समाजशास्त्र का अध्ययन करने, पढ़ाने और उनमें शामिल होने के पीछे मनोस्थिति का अध्ययन दशकों तक करने के बाद, मैं इस विरोध का विश्लेषण अकादमिक और राजनीतिक, दोनों नजरियों से किए बिना नहीं रह सकाय क्योंकि इसमें वे कई खूबियां थीं जिसकी तलाश श्नव सामाजिक आंदोलनोंश् के सिद्धांतकार लोकतांत्रिक संघर्षों में करते हैं। सिर्फ लिखित सामग्री बांटने वाले या वर्ग-हितों के आधार पर होने वाले पारंपरिक आंदोलनों के उलट, यह जनांदोलन लोकतंत्र की जगह, संवैधानिक नैतिकता व नागरिकता की गरिमा बहाल करने के बारे में भी उतना ही था। एलेन टुरेन का तर्क कि ऐसे आंदोलन समाज की दिशा तय करने के लिए आखिरी उपाय होते हैं- यानी उन मूल्यों को परिभाषित करना,जिनके साथ लोग जीना चाहते हैं-यह मुहिम ठीक उसे परिभाषित करती लगी जो ये युवा हासिल करना चाह रहे यअल्बर्टो मेलुची की अंतर्दृष्टि कि ऐसे अवसरों पर ताकत संगठनात्मक पदानुक्रम के बजाय सामूहिक पहचान व साझा अर्थों से चालित होती है,वह यहां साफ दिखी कि कैसे अजनबी लोग एक साझे मकसद हेतु साथी बन गए।

फिर भी, मेरे मन में जो बात सबसे ज्यादा बनी है, उसका संबंध ढांचे के बारे में अधिक न होकर

उस बिंदु पर है जो इस पहली बड़ी लामबंदी ने अपने बारे में साबित किया- और यहां बीते कुछ दिनों में हुआ दमन जाने-अनजाने, इस आंदोलन का सबसे मजबूत सबूत बन गया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना, हुजूम में भी इतना जुड़ाव, पर्याप्त सबूत है कि यह आंदोलन मात्र प्रभाव बनाने के लिए किया गया दिखावटी विरोध नहीं। इसके स्वरूप में असल शिकायतों और सच्ची प्रतिबद्धता से उपजी झलक है। न कि वह जिसकी उम्मीद सरकारें अक्सर करती हैं, कि क्या यह आंदोलन क्षणिक चिंगारी है जो जल्द बुझ जाएगी। सबसे बड़ी बात यह कि जिस सुबह इसके सबसे जाने-पहचाने चेहरे को हिरासत में लेकर ले जाया गया, तब भी समूह ने न तो कोई गलती की, न ही बिखरा, बल्कि अपनी जगह शांति और संयम के साथ बनाए रखी, जो वह परिपक्वता, दृढ़ संकल्प दर्शाती है, वे खूबियां जिन्हें अक्सर युवाओं से जोड़कर नहीं देखा जाता। इसने दर्शा दिया कि आंदोलन मुख्य नेता के बिना भी चल सकता है। आंदोलन जो शनिवार सुबह अपने सबसे प्रमुख चेहरे को खोने के बाद भी सप्ताहांत भर डटा रहा, और फिर सोमवार को संसद तक मार्च कर सका, क्योंकि इस सवाल का जवाब देने का संकल्प कर रखा था कि क्या टिके रहना किसी एक व्यक्ति पर निर्भर है।

एकत्र होने की भावना इसलिए इतनी व्यापक हो पाई कि इसने नागरिकों के बहुत बड़े वर्ग की नब्ज को छुआय हर कोई अपनी-अपनी चिंताओं की वजह से आया, यहां उन्हें अपनी चिंताओं हेतु साझा भाषा मिली। जाहिर है कि तमाम व्यवस्थाओं को धीरे-धीरे खोखला किया जा रहा, और शिक्षा- जो किसी गणतंत्र द्वारा अपने युवाओं से किया गया सबसे बुनियादी वादा होता है- गिरावट की सबसे बड़ी मिसाल बन गई । तंत्र चलाने वाली सरकार वही है जिसका अनशनरत छात्रों के प्रति रवैया-जैसा आज बेरहमी से साफ हो गया- लाठी व आंसू गैस के गोले बरसाना है।

इस भीड़ को व्यापकता देने वाला एक अंश यह भी कि जो शिकायतें अमूमन अलग-अलग रहती थीं, यहां आकर साझा दुख बन गई। सबसे फौरी हैं लोकतांत्रिक चिंताएं। नागरिकता सिद्ध करने का संकट कई तरह से महसूस किया जा रहा-कौन नागरिक है या किसका हक है, इसको लेकर अनिश्चितता हो या असहमति के लिए कम होती जगह या फिर यह भावना बनना कि आम नागरिक की आवाज की अहमियत घट रही है। इसके साथ अन्य सामाजिक चिंताएं भी हैं। विविधतापूर्ण समाज को बांधे रखने वाले ताने-बाने पर लगातार पड़ रहा दबाव, जानबूझकर दिया जा रहा ध्रुवीकरण को बढ़ावा और रोजमर्रा का शिष्टाचार खत्म होते किसने महसूस नहीं किया? इन सबके पीछे वे आर्थिक दबाव हैं जिनका सबसे ज्यादा असर युवाओं पर होता है। वे बढ़ती बेरोजगारी, असमानता और जीवन-यापन की बढ़ती लागत जैसी कई चुनौतियों से जूझ रहे। अलग-अलग वजहों से पैदा हुई शिकायतों का यहां एक साथ आना संकेत है कि यह कोई सीमित विरोध-प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक व्यापक लोकतांत्रिक चिंता है।

यही वजह है कि मुझे नहीं लगता कि यह आंदोलन जल्द खत्म होने वाला है। सरकारें अक्सर मान लेती हैं कि विरोध-प्रदर्शन बस कुछ समय के लिए होने वाली अस्थाई हलचल हैं, जिन्हें गिरफ्तारियों, थकाकर कमजोर करके या प्रशासनिक पाबंदियों के जरिए संभाला जा सकता है। सामाजिक आंदोलनों के जानकार बार-बार ऐसी सोच के ख़तरे बारे चेताते आए हैं। जब कोई आंदोलन एक साझा लोकतांत्रिक पहचान बनाने में सफल हो जाता है, तो उसमें अलग-अलग जगहों और पीढ़ियों के बीच खुद को फिर से पैदा करने की क्षमता बन जाती है। तब यह किसी एक जगह या कुछ गिने-चुने नेताओं पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि यह संवाद, रिश्तों और सामूहिक यादों में रच जाता है।

मनोज कुमार झा

भौतिक स्थलों पर नियंत्रण किया जा सकता है या वहां बैरिकेड लगाए जा सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को नहीं रोका जा सकता। हम यह नहीं भूलें कि दमन की हर कार्रवाई में ऐसे नागरिकों का दायरा बढ़ने की संभावना होती है जो सत्ता, न्याय और संवैधानिक नागरिकता के बारे में और मुश्किल सवाल पूछने लगेंगे। हम पहले से ही देश के विभिन्न भागों में इस किस्म के विरोध-प्रदर्शन होते देख रहे हैं।

दो दिनों की अपनी उपस्थिति के दौरान वहां मेरी मुलाकात जिन युवाओं से हुई, उन्होंने मुझमें यकीन जगाया कि यदि वे समावेशिता, नैतिक साहस और लोकतांत्रिक एकजुटता की इस भावना को बनाए रखते हैं, तो यह आंदोलन न सिर्फ कायम रहेगा, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की नैतिक शब्दावली को भी समृद्ध करेगा। हर टिकाऊ सामाजिक आंदोलन वर्तमान के विरोध से परे होता है। यह अधिक न्यायपूर्ण भविष्य की कल्पना करने का निमंत्रण भी होता है।

चुनावों से इतर, लोकतंत्र उन नागरिकों के जरिए खुद को नया रूप देता है जो उम्मीद नहीं तजते और साझी करुणा के आधार पर एकजुट हो जाते हैं। वे यह समझते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि संविधान प्रदत वादा एक जीवंत सच्चाई बना रहना चाहिए।

राहुल गांधी की गिरफ्तारी और नीट छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन

माही की गूंज, आलीराजपुर।

दिल्ली में नीट अभ्यर्थियों पर किए गए लाठीचार्ज तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आलीराजपुर जिले के सभी प्रमुख तहसील एवं ब्लॉक मुख्यालयों पर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए इसे लोकतंत्र, संविधान और युवाओं की आवाज को कुचलने का प्रयास बताया।

जिला मुख्यालय आलीराजपुर में पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल तथा जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओमप्रकाश राठौर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं जोबट में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद डावर, उदयगढ़ में नगर सिंह वसुनिया तथा चंद्रशेखर आजाद नगर में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हरीश भाबर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालयों पर धरना देकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश का युवा आज अपने भविष्य को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, लेकिन भाजपा सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन पर लाठियां बरसा रही है। नीट परीक्षा में अनियमितताओं और पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य संकट में पड़ गया है, लेकिन सरकार दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय आंदोलनरत छात्रों को दबाने का काम कर रही है।

नेताओं ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज से घबराकर दमनकारी नीतियां अपना रही है। राहुल गांधी लगातार युवाओं, किसानों, आदिवासियों, बेरोजगारों और गरीबों की आवाज संसद से लेकर सड़क तक उठा रहे हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए दमन और डर का माहौल बना रही है।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग की कि नीट परीक्षा से जुड़े पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कठोर सजा दी जाए, छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो तथा राहुल गांधी की गिरफ्तारी को तत्काल वापस लिया जाए।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार शिक्षा, रोजगार, महंगाई, किसानों की समस्याओं और युवाओं के भविष्य जैसे गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जनता के अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी।

आलीराजपुर में रहे उपस्थित

ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश पचाया, तरुण मंडलोई, सुरेश सारडा, अंगर सिंह चौहान, मुकेश, अरविंद पटेल, सोंडवा ब्लॉक अध्यक्ष सुरसिंह, पार्षद समर्थमल राठौड़ सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

जोबट में रहे उपस्थित

कालू मेड़ा, निर्मल (मोनू) बाबा, आराम पटेल, विक्रम पटेल, लखन सरपंच सलखेड़ा, रणजीतगढ़ सरपंच, कारण भाई, दिलीप, चंदर सिंह, दिलीप चौहान (थापली सरपंच), युवक विधानसभा अध्यक्ष लक्की राठौर, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश देवका, सोयब खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे।

उदयगढ़ में रहे उपस्थित

ज्ञान सिंह मुजल्दा, विधायक प्रतिनिधि पान गोला, सरपंच थानसिंह डावर, कुंवर सिंह खराड़ी, नाथू सिंह खराड़ी, बाथू बघेल, कलम सिंह, गुमान सिंह, विजय मेहड़ा, राजू डेहदिया, धनसिंह, विक्रम पटेल, ढुड़िया भाई सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

चंद्रशेखर आजाद नगर में रहे उपस्थित

लाइक शेख, मदन डावर, राजेश जैन, अश्विन, भरता भाई, बाबू मावी, कपिल सोनी सहित अनेक कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए।

प्रदर्शन में जिलेभर के कांग्रेस पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई,तथा विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि युवाओं, छात्रों, किसानों और आम जनता के हितों पर किसी भी प्रकार का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखेगी।

सामूहिक दुष्कर्म एवं डकैती प्रकरण के 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार

माही की गूंज, आलीराजपुर।

पुलिस अधीक्षक जिला अलीराजपुर रघुवंश सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति उमठ बघेल के निर्देशन में एसडीओपी जोबट आशुतोष के नेतृत्व में दिनांक 10-11 जुलाई 2026 की दरमियानी रात्रि थाना बोरी क्षेत्रांतर्गत घटित सामूहिक दुष्कर्म एवं डकैती की गंभीर घटना के उपरांत पुलिस द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। धरपकड की लगातार की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप उक्त प्रकरण सहित अन्य लंबित मामलों में फरार, ईनामी एवं स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसी क्रम में सामूहिक दुष्कर्म एवं डकैती के प्रकरण में 2 फरार मुख्य आरोपी नरू ऊर्फ नरपत पिता कालु मेहडा भील 20 वर्ष, निवासी ग्राम बयडा एवं जितेन्द्र पिता सोमसिंह चौहान भील उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बीड बडी को दिनांक 21 जुलाई 2026 को बोरी पुलिस टीम के द्वारा दबीश देकर गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार आरोपियों से लूटे गये चांदी के आभुषण कीमती 28 हजार रूपये एवं घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल सहित 01 धारदार फालिया जप्त किया गया है। उक्त घटना में अबतक कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा शेष 2 आरोपियों की गिरफ्तार हेतु 2 टीमें गिरफ्तार सुनिश्चित करने हेतु लगातार कार्यवाही कर रही है।

अमृत फुहारों से कृषकों तथा फसलों को राहत

माही की गूंज, आम्बुआ।

क्षेत्र में विगत दो दिनों से रूक रूक कर हल्की रिमझिम बारिश हो रही है जिससे मुरझाती फसलों और कृषिकों के चहरों पर कुछ रोनक लौट आई है, क्षेत्र में भारी बारिश की जरूरत महसूस की जा रही है। विगत लगभग एक पखवाड़े से क्षेत्र में वर्षा नहीं होने से खेतों में अभी कई किसानों ने बुआई नहीं की है और जिन्होंने बुआई कर दी है उन के खेतों में उग आए पौधे सूखने की कगार पर पहुंच गए थे और कृषक दिन रात प्रार्थना कर रहे थे कि बारिश हो जाए , शायद उनकी प्रार्थना का असर है कि रिमझिम ही सही पर बारिश हो रही है, जिससे फसलों तथा किसानों को राहत मिली है आगामी दिनों में अच्छी वर्षा की प्रार्थना की जा रही है ताकि फसलों को फायदा हो तथा जलाशयों में जल संग्रह हो सके जिससे भविष्य में जल संकट का सामना न करना पड़े। आषाढ़ मास में इन दिनों सावन माह जैसी फुहारें पड़ रही है।

नमाज की जगह को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष

माही की गूंज, धार।

जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर से जुड़ा विवाद एक बार फिर देश की सबसे बड़ी अदालत की चौखट पर पहुंच गया है। इस बार विवाद शुक्रवार की नमाज के लिए तय की गई जगह को लेकर खड़ा हुआ है।

मुस्लिम पक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया है कि अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद स्थानीय प्रशासन उन्हें नमाज अदा करने के लिए काफी दूरी पर जगह आवंटित कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को स्वीकार करते हुए मामले पर आगामी शुक्रवार को सुनवाई करने की सहमति दे दी है।

प्रशासन पर आदेश के उल्लंघन का आरोप

बुधवार को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ (जिसमें न्यायमूर्ति जोयमाल्या बाग्ची भी शामिल हैं) के समक्ष मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने इस मुद्दे को उठाया।

अहमदी ने पीठ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में भोजशाला के पास ही नमाज के लिए कोई खुली जगह मुहैया कराने को कहा था। हालांकि, प्रशासन ने जो स्थान चिन्हित किया है, वह भोजशाला से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। इसलिए इस मामले पर त्वरित सुनवाई की जाए।

2 किलोमीटर नहीं, केवल 900 मीटर दूर है जगहः सॉलिसिटर जनरल

मुस्लिम पक्ष के दावों पर राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दूरी के आंकड़े को खारिज किया। उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा दी गई जगह 2 किलोमीटर नहीं, बल्कि मात्र 900 मीटर की दूरी पर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर किसी प्रकार का विवाद नहीं चाहती और वे खुद व्यक्तिगत रूप से इस विषय को देखकर सुलझाने का प्रयास करेंगे।

पीठ में शामिल न्यायमूर्ति जोयमाल्या बाग्ची ने इस दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत के आदेशों का पालन उसकी मूल भावना और अक्षरशः होना चाहिए।

क्या है पूरा मामला?

हाई कोर्ट का निर्णयरू मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने धार स्थित विवादित संरचना की धार्मिक प्रकृति पर निर्णय देते हुए इसे वाग्देवी (मां सरस्वती) का मंदिर घोषित किया था। वहीं, मुस्लिम समुदाय इसे श्कमाल मौला मस्जिदश् मानता है।

सुप्रीम कोर्ट में चुनौतीरू हाई कोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम पक्ष ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।

अंतरिम व्यवस्थारू सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर पूर्ण रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को निर्देश दिया था कि बिना अदालत की अनुमति के परिसर में कोई ढांचागत बदलाव न किया जाए।

नमाज की व्यवस्थारू इसी सुनवाई के दौरान अदालत ने परिसर के पास ही मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार की नमाज पढ़ने के लिए उपयुक्त व खुली जगह उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था, जिसे लेकर अब दूरी का नया विवाद खड़ा हो गया है।

जनगणना के चलते 2027 से पहले नागदा जिला गठन पर अंतिम फैसला नहीं

माही की गूंज, नागदा।

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के औद्योगिक नगर नागदा को नया जिला बनाए जाने की प्रक्रिया अभी जारी है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय वर्ष 2027 की जनगणना के बाद ही संभव होगा। विधानसभा में बुधवार को सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रस्ताव से संबंधित दावे-आपत्तियों का निराकरण कर प्रतिवेदन मध्यप्रदेश पुनर्गठन आयोग को भेज दिया गया है। आयोग की अनुशंसा मिलने के बाद ही शासन अंतिम निर्णय ले सकेगा।

विधानसभा में हरदा से कांग्रेस विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने के तारांकित प्रश्न के उत्तर में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि नागदा जिला गठन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई पूरी कर संशोधित प्रतिवेदन मध्यप्रदेश पुनर्गठन आयोग को भेजा जा चुका है। हालांकि आयोग की अंतिम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की जा सकी है।

सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि वर्ष 2027 में प्रस्तावित जनगणना के मद्देनजर मार्च 2027 तक राज्य की प्रशासनिक सीमाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा। ऐसे में नागदा को जिला बनाने का अंतिम निर्णय जनगणना प्रक्रिया के बाद ही लिया जा सकेगा।

विधानसभा में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश पुनर्गठन आयोग अब तक प्रदेश के 38 जिलों का भ्रमण कर चुका है। उज्जैन जिले का दौरा अगस्त-सितंबर 2026 में प्रस्तावित है। चूंकि नागदा जिला गठन का मामला उज्जैन जिले से संबंधित है, इसलिए आयोग का यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राजस्व मंत्री ने बताया कि नागदा को जिला बनाने के लिए 28 जुलाई 2023 को प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई थी। इसके बाद प्राप्त दावे और आपत्तियों का परीक्षण कर 15 सितंबर तथा 4 अक्टूबर 2023 को शासन को प्रतिवेदन भेजा गया। शासन के निर्देशों के अनुरूप संशोधित प्रतिवेदन भी पुनर्गठन आयोग को उपलब्ध कराया जा चुका है।

सरकार ने यह भी जानकारी दी कि मध्यप्रदेश पुनर्गठन आयोग का गठन 12 मार्च 2024 को किया गया था। बाद में आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर 12 मार्च 2027 तक कर दिया गया है। आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने के बाद ही नागदा जिला गठन के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि नागदा को जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। वर्ष 2020 में तत्कालीन राज्य सरकार ने नागदा, मैहर और चाचौड़ा को नए जिले बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। बाद में वर्ष 2023 में नागदा के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई। इस बीच मैहर और पांढुर्णा को जिला घोषित किया जा चुका है, जबकि नागदा का प्रस्ताव अभी अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा में है।

नशे से दूरी है जरूरी 2.0

माही की गूंज, आम्बुआ।

पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार प्रदेशभर में संचालित नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के अंतर्गत थाना आम्बुआ क्षेत्र के बस स्टैंड पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आमजन को नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे जनजागरूकता अभियान के तहत मध्यप्रदेश में 15 जुलाई से नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान संचालित किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशन में प्रदेशभर में विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक आलीराजपुर रघुवंश सिंह के निर्देशन पर आम्बुआ में मंगलवार को हाट बाजार में बस स्टैंड पर आम्बुआ थाना प्रभारी मोहन डावर की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कलाकारों ने नशे के दुष्परिणामों का प्रभावी मंचन करते हुए आमजन को नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवन अपनाने तथा समाज को नशामुक्त बनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों ने भी नशे के विरुद्ध जनजागरूकता अभियान में सहयोग देने का संकल्प लिया।

आम्बुआ पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे स्वयं नशे से दूर रहें तथा अपने परिवार एवं समाज को भी नशा मुक्त बनाने में सक्रिय सहभागिता निभाएं।

थाना के उत्कृष्ट अनुसंधान से हत्या के आरोपी को न्यायालय से सजा

माही की गूंज, आम्बुआ।

थाना आम्बुआ के अपराध क्रमांक 119/2025, धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दर्ज हत्या के एक गंभीर प्रकरण में थाना आम्बुआ पुलिस द्वारा किए गए उत्कृष्ट एवं संवेदनशील अनुसंधान के परिणामस्वरूप न्यायालय से आरोपी को दोषसिद्ध कर दंडित कराया गया है।

घटना दिनांक 06 मई 2025 को ग्राम खण्डाला डावरी फलिया में उस समय घटित हुई, जब फरियादी मुलेश पिता अमरसिंह जमरा भीलाला अपने पिता अमरसिंह जमरा भीलाला एवं अन्य परिजनों के साथ एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। इसी दौरान आरोपी राजू पिता मंगु जमरा भीलाला, निवासी ग्राम खण्डाला पुजारिया फलिया, हाथ में बांस का डंडा लेकर वहां पहुंचा तथा पुरानी रंजिश के चलते अमरसिंह पर जान से मारने की नीयत से सिर पर लगातार डंडों से हमला कर दिया। हमले में अमरसिंह गंभीर रूप से घायल होकर अचेत हो गए, जिन्हें तत्काल 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय आलीराजपुर ले जाया गया। चिकित्सकों द्वारा गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें उच्च उपचार हेतु दाहोद रेफर किया गया, किन्तु उपचार के लिए ले जाते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना आंबुआ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस अधीक्षक आलीराजपुर के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्योति उमठ बघेल, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जोबट आशुतोष के मार्गदर्शन में उक्त प्रकरण को चिन्हित श्रेणी में लेकर थाना प्रभारी उप निरीक्षक मोहनसिंह डावर द्वारा अत्यंत संवेदनशीलता के साथ वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान घटना के प्रत्येक पहलू का सूक्ष्म परीक्षण कर पर्याप्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य संकलित किए गए तथा अभियोग पत्र समय-सीमा में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के विचारण के दौरान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के.एम. कनाश द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। वहीं प्रधान आरक्षक अमरसिंह भाबर, आरक्षक राकेश एवं आरक्षक टीकम द्वारा गवाहों एवं साक्षियों से सतत संपर्क बनाए रखते हुए उन्हें मान. न्यायालय में उपस्थित कराकर सशक्त एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत कराए गए। मामले की सुनवाई माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आर.पी. सेवेतिया के न्यायालय में हुई। प्रकरण की सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर पर माननीय न्यायालय ने आरोपी राजु जमरा पिता मंगु जमरा भीलाला उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम खण्डाला पुजारिया फलिया को दोषी पाया। माानीय न्यायालय ने हत्या की धारा -103(1) बी.एन.एस. में आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया एवं 10 माह तक सश्रम कारावास की सजा दी गयी।

थाना आम्बुआ पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार को मध्यप्रदेश शासन की पीड़ित प्रतिकर योजना-2015 का लाभ दिलाये जानें हेतु उक?त घटना पीड़ित परिवार से संपर्क कर आवेदन प्राप्त किया जा रहा है, जिससे उन्हें पीडित प्रतिकर योजना 2015 के तहत शासन की ओर से 4.50 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह ने इस महत्वपूर्ण चिन्हित प्रकरण में उत्कृष्ट अनुसंधान कर आरोपी को सजा दिलाने पर अनुसंधान अधिकारी उप निरीक्षक मोहनसिंह डावर एवं उनके अधीनस्थ टीम को पृथक से पुरस्कृत करनें की घोषणा की है।

हर कदम पर है (शराब) नशे की दुकान तो कैसे होगी नशे से दूरी...? यह सोचना है जरूरी

हर साल पुलिस, प्रशासन की नौटंकी स्कूली बच्चों को ज्ञान देने के साथ हो जाती है समाप्त

माही की गूंज, झाबुआ।
मुजम्मिल मंसुरी

यह एक ऐसी नौटंकी है जो हर साल 15 जुलाई से पुलिस और प्रशासन को करना पड़ती हैं। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि, पुलिस और प्रशासन साल भर में ऐसे कई नौटंकियों को अंजाम देते रहे है। यातायात सप्ताह और नशा मुक्ति अभियान इसका सीधा सा उदाहरण है। वर्षों से चले आ रहे इन अभियानों के परिणाम को अगर देखें तो स्वतः ही अंदाजा हो जाएगा कि, यह कोई अभियान नहीं हैं, महज माथा उतारनी और नौटंकी भर है। हालांकि इन अभियानों के उद्देश्य जिस तरह के बताए जाते है वह सिर्फ और सिर्फ दूर की कोड़ी ही नजर आ रहे है। क्योंकि जब तक मूल समस्या की जड़े बाकी रहती है वह समस्या कभी खत्म नहीं हो सकती। और सरकारों और उनके तंत्र को इस तरह के अभियान चलाकर जड़े काटने की इजाजत तो शायद सरकारें कतई तौर पर दे ही नहीं सकती। वजह यह कि अगर नशे की किसी भी तरह के अभियान के दौरान अगर जड़े काट दी गई तो सरकारों के राजस्व में भारी गिरावट आ जाएगी जो कि सरकार खुद नही चाहती।

इस साल फिर 15 जुलाई से पुलिस और प्रशासन मिलकर बखूबी नौटंकी निभाने का अभिनय कर रहे है। प्रदेश के सभी जिलों में 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन और पुलिस की नौटंकी ऐसी है कि वे इस अभियान को लेकर कहीं नुक्कड़ नाटक करते दिखाई दे रहे है तो कहीं उन नाबालिग स्कूली विद्यार्थियों के बीच चर्चा कर रहे है जिन्हे नशे से कोई सरोकार नहीं है। हर कदम पर है शराब व नशे की दुकान तो कैसे होगी नशे से दूरी... यह पहले सोचना है जरूरी लेकिन प्रशासन, पुलिस और सरकार उन अवैध नशे के अड्डों को खत्म करने में नाकाम है जहां से खुलेआम नशे का व्यापार होता है। यह कैसे संभव है कि नशे की दुकानों को बंद किए बिना प्रदेश को नशामुक्त बनाया जा सके... !

बात अगर आदिवासी बाहुल जिले की करें तो जहां नशीले पदार्थों का सेवन परंपरागत रूप से किया जाता हो वहां इस तरह के अभियान या उसकी नौटंकी का क्या ही मतलब रह जाता है...? आदिवासी बाहुल जिलों में जहां गम हो या खुशी मदिरा की धार दिए बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। वहां इस तरह के अभियान पुलिस और प्रशासन की नौटंकी ही साबित होंगे या यूं कह लें कि, इस तरह के क्षेत्रों में प्रशासन और पुलिस अभियान के नाम पर महज माथा उतारनी ही करती दिखाई देती है।

जबकि इन्ही आदिवासी जिलों की अगर बात करें तो इन क्षेत्रों में शायद ही ऐसी कोई दुकान होगी जहां धुम्रपान या नशीले पदार्थ ना मिलते हो। ग्रामीण क्षेत्रों में तो हालात ऐसे है कि, एक ही दुकान पर हर चीज की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। फिर चाहे वह बीड़ी, सिगरेट हो, पाउच, गुटखा या खेनी हो, या फिर देशी, विदेशी शराब ही क्यों ना हो सबकुछ आसानी से एक ही छत के नीचे मिल जाता है। कहने वाले कहते है कि, जहां चखना

मिलता है वहां दारू तो मिल ही जाती है।

महज झाबुआ जिले की अगर बात करें तो यहां की अंग्रेजी और देशी शराब दुकानों के ठेके अरबों रुपए में होते है। जिले में इन कंपोजिट शराब दुकानों की संख्या महज 33 है मगर इन दुकानों की कीमतें बताते है कि सिर्फ 33 दुकानों से अरबों रुपए का राजस्व सरकार को मिलता है। तो फिर सरकार इन दुकानों को बंद करने से तो रही। मगर इसके विपरीत जिले की स्थिति कुछ और ही नजर आती है। यह 33 शराब दुकानें तो वह है जो सरकारी रिकार्ड पर मौजूद है, लेकिन जिले में चल रही अवैध शराब दुकानों का आंकड़ा नशा मुक्ति अभियान चलाने वाले प्रशासन या पुलिस के पास भी नहीं होगा। माही की गूंज यहां इस बात का दावा करती है कि, जिले में लायसेंसी शराब दुकानों के अलावा लगभग 6 से 7 हजार अवैध शराब बिक्री के ऐसे ठीये मौजूद है जो हर दिन लाखों की अवैध शराब खपा देते है। ऐसा नहीं है कि स्थानीय पुलिस को इन अवैध शराब दुकानों या ठीयों के बारे में जानकारी नहीं है। मगर सबका अपना -अपना पेट है, वैसे ही पुलिस का भी अपना पेट है। ऐसे कई प्रणाम मौजूद है जो यह सिद्ध करते है कि, अवैध शराब दुकानों व ठीयों से पुलिस व आबकारी को बंदी जाती है। खुद पुलिस इन्हे इतना संरक्षण देती है कि, जहां लाखों का अवैध शराब का जखीरा पकड़ा जाता है वहां महज कुछ पेटी का केश पुलिस द्वारा अवैध शराब दुकान या ठीये के मालिक से सांठ-गांठ कर बना दिया जाता है। उस पर भी सितम यह कि ऐसे मामलों में कभी भी आरोपी मुख्य शराब माफिया को नहीं बनाया जाता बल्कि उसके यहां काम करने वाले नौकरों के नाम प्रकरण बनाए जाते है। माही की गूंज हमेशा से जिले में शराब माफियाओं के खिलाफ मुखर रहा है और ऐसी कई खबरें प्रकाशित कर चुका है जो पुलिस और माफियाओं के गठजोड़ को सरेआम उजागर करती रही है। जिले में शराब के अलावा भी कई तरह के नशे युवाओं के नशों में हद से ज्यादा बह निकले है। ब्राउन शुगर, गांजा, एमडी ड्रग्स और कई तरह की मेडीशन नशे में इस्तेमाल हो रही है। अब जिले में जुम्बी नशे की धमक भी महसूस की जा सकती हैं। जुम्बी एक ऐसा नशा है जो इंसान को नशा करने के बाद घंटो स्थिर कर देता है और नशा करने वाला एक ही मुद्रा में घंटो निकाल देता है। लेकिन पुलिस और प्रशासन जिले में इन नशाखोरों और माफियाओं की जड़े काटने में हमेशा से ही नाकाम दिखाई दिया है।

अब सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन और पुलिस 15 जुलाई से पीपड़ी लेकर हर साल निकल पड़ते है। 'नशे से दूरी है जरूरी' का नारा उन बच्चों के माथे मढ़ा जाता है जिन्हे अभी नशे के बारे में कुछ खास जानकारी ही नहीं है। जो नशे से अनभिज्ञ है और प्रारम्भिक शिक्षा में लगे हुए है। ऐसे बच्चों के बीच पहुंच कर प्रशासन और पुलिस अपनी पीपड़ी बजाता और अपनी ढपली अपना राग अखबारों में प्रकाशित करवाता नजर आता है। जबकि हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। इस अभियान के तहत अब तक एक भी खबर ऐसी नहीं निकल कर आई कि कहीं पर पुलिस या प्रशासन नशे से जुड़ी कोई बड़ी कार्रवाई की हो। हालांकि जिला सीमावर्ती होने के चलते यहां अवैध शराब से भरे वाहन पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हालात यह बताते है कि, पुलिस स्थानीय शराब ठेकेदारों की मुखबिरी पर बाहरी शराब ठेकेदारों की ही शराब पकड़ती है। इसके अलावा जिले में स्थानीय स्तर पर जो छुट-पुट कार्रवाईयां होती है वह तो सिर्फ मू... में मछली मारने जैसी कही जा सकती है। जबकि जिले के हर गांव में अवैध शराब के कम से कम दस ठीये आसानी से मिल जाएंगे। मगर पुलिस व प्रशासन को यह दिखाई नहीं देते।

कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि सरकार के इस तरह के अभियानों को लेकन पुलिस और प्रशासन सिर्फ और सिर्फ नौटंकी ही करते दिखाई देते है। मूल जड़ को समाप्त करने की कोई ठोस योजना न इनके पास है और ना ही इनके बस में। क्योंकि अगर जिले को नशा मुक्त करना है तो फिर जड़ों को काटना अत्यंत ही जरूरी है। सरकारों को इन सारी कंपनियों को बंद करना होगा जो शराब, गुटखा-पाउच, खेनी, बीड़ी, सिगरेट और इसी तरह के कई अन्य नशीले पदार्थों का उत्पादन करती है। मगर यह सब जानते है कि इन कंपनियों को बंद करने का क्या मतलब है...?

अनदेखी: प्राथमिक शाला परिसर में बने पेशाब घर व शौचालय अनुपयोगी

माही की गूंज, खवासा।
सुनील सोलंकी

जहां सर्व शिक्षा अभियान के तहत छात्र-छात्राओं को शासकीय स्कूलों में सभी मूलभूत सुविधाओ के साथ उच्च शिक्षा देने का दावा सरकारों द्वारा किया जाता रहा है। वहीं सरकार एवं प्रशासनिक नुमाइंदों की अनदेखी के चलते कई ग्रामीण स्कूलों में मूलभूत सुविधा के तहत शौचालयो की कमी है। तो कहीं शौचालय व पेशाब घर बनाए तो गए हैं लेकिन अनदेखी व रखरखाव के अभाव में वह जर्जर होकर अनुपयोगी पड़े हैं। ऐसे में स्टाफ के साथ छात्र-छात्राओं को पेशाब घर व शौचालय की अनपयोगिता के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

जिसका एक छोटा सा उदाहरण थांदला शिक्षा केंद्र के चापानेर संकुल के अंतर्गत ग्राम पंचायत पाटडी के डामर फलिये में देखने को मिलता है। यहां पर बनी प्राथमिक शाला में करीब 38 बच्चे अध्यनरत है। डामर फलिया प्राथमिक शाला परिसर में बने दो पेशाब घर व शौचालय है। बताया जाता है कि, यह पेशाब घर व शौचालय करीब 5-7 वर्षों पूर्व ही बनाए गए थे लेकिन रखरखाव के अभाव में कुछ वर्षों में ही यह जर्जर होकर अब अनुपयोगी अवस्था में पड़े हैं।

यहां पदस्थ एक शिक्षक ने अपना नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया कि, शौचालय की स्थिति काफी दयनीय है बच्चे बाहर खुले में ही पेशाब करने व शोच करने हेतु जाते हैं। उक्त समस्या के संबंध में जनशिक्षक व वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत करवाया गया है लेकिन किसी के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

यहां नए शौचालय की अत्यंत आवश्यकता है प्रशासन को इस और ध्यान देना चाहिए उक्त बात स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही है।

दोनों पेशाब घर व शौचालय अनुपयोगी होकर इस तरह से खंडर व जर्जर अवस्था में है।

शिक्षकों की कमी से जूझते बच्चे, स्कूलों में अतिथि भर्ती को लेकर विभाग की लापरवाही उजागर

नवीन सत्र के एक माह से अधिक समय के बाद अतिथि भर्ती नहीं, स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित

माही की गूंज ,पेटलावद।

प्रदेश में प्रत्येक वर्ष नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ शिक्षक विहीन शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाती रही है। ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो। इस व्यवस्था से उन स्कूलों को राहत मिलती थी जहां नियमित शिक्षकों के पद रिक्त हैं। लेकिन इस वर्ष स्थिति अलग दिखाई दे रही है। 16 जून से नवीन सत्र शुरू होने के बाद जुलाई का महीना समाप्ति की ओर है, इसके बावजूद शासन और शिक्षा विभाग द्वारा अब तक अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। इससे न केवल स्कूल प्रबंधन बल्कि हजारों विद्यार्थी और अतिथि शिक्षक बनने की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी भी असमंजस की स्थिति में हैं।

कई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी

सूत्रों के अनुसार पेटलावद विकासखंड के कई प्राथमिक, माध्यमिक और हाईस्कूल स्तर के विद्यालय आज भी शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। कहीं एक ही शिक्षक पूरे विद्यालय का संचालन कर रहा है तो कहीं महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक नहीं होने से विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है।

जानकारी के अनुसार विकासखंड के कई विद्यालयों में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी सहित अन्य विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। कई स्थानों पर एक या दो नियमित शिक्षकों के भरोसे पूरी शाला संचालित की जा रही है। ऐसे में एक ही शिक्षक को अलग-अलग कक्षाओं को पढ़ाने के साथ-साथ प्रशासनिक कार्य भी संभालने पड़ रहे हैं। इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चुनौती बन गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावकों का कहना है कि, यदि जल्द शिक्षकों की व्यवस्था नहीं हुई तो विद्यार्थियों की पढ़ाई और आगामी परिक्षाओं पर गंभीर असर पड़ सकता है। हर वर्ष अतिथि शिक्षकों की भर्ती से रिक्त पदों पर अस्थायी रूप से शिक्षण व्यवस्था सुचारु हो जाती थी, लेकिन इस बार भी पिछले सत्र की तरह भर्ती में हो रही देरी ने बेरोजगार योग्य अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर भी असर डाला है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि विद्यालयों में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षा विभाग की ओर से अब तक भर्ती प्रक्रिया को लेकर कोई स्पष्ट समय-सीमा घोषित नहीं की गई है, जिससे असमंजस और बढ़ गया है।

क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों ने शासन से मांग की है कि शिक्षक विहीन विद्यालयों में शीघ्र अतिथि शिक्षकों की भर्ती कर शिक्षण व्यवस्था को पटरी पर लाया जाए। उनका कहना है कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय में किसी भी प्रकार की देरी का खामियाजा अंततः विद्यार्थियों को ही भुगतना पड़ता है।

इस संबंध में बीईओ देवेंद्र ओझा से चर्चा की तो उनका कहना है कि, प्रक्रिया पूरी हो गई है जल्द ही अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।

मूलभूत सुविधाओं का अभाव, पंचायत अपने परिसर में बनी दुकानों में लोगों को खड़े-खड़े मुतवा रही

माही की गूंज, काकनवानी।
नरेश पंचाल

कहते हैं किसी भी गांव के विकास व उसकी सुंदरता ग्राम के प्रवेश द्वार या स्थानीय निकाय के परिसर व भवन की बनावट व उसकी रूपरेखा को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उक्त गांव की सुंदरता व विकास का स्तर क्या व केसा होगा।

जी, हां पलवाड़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत के काकनवानी की बात करें तो यह क्षेत्र कांग्रेसी समर्थक था। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत काकनवानी में गत ग्राम पंचायत चुनाव के पहले कई वर्षों तक कांग्रेस ने अपना कब्जा बनाए रखा था। लेकिन मध्य प्रदेश व उसके बाद केंद्र में भी भाजपा की सरकार होने के चलते ग्राम पंचायत काकनवानी का विकास न होने का कारण प्रदेश सरकार द्वारा कांग्रेसी पंचायतो को फंड आवंटित नहीं करने का कारण बताकर यहां विकास का अभाव था। जिसके चलते स्थानीय निवासियों ने गत चार वर्ष पूर्व हुए ग्राम पंचायत चुनाव में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाते हुए भाजपाइयों को विकास की उम्मीद के साथ जनादेश दिया था। लेकिन काकनवानी पंचायत के नुमाइंदे ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद मूलभूत सुविधाओं को भी नहीं दे पा रही है। जिससे कहीं न कहीं ग्रामवासियो में निराशा ही हाथ लगी है। गांव में न तो स्ट्रीट लाइट सुचारू रूप से चालू है, न ही सफाई, न हीं नल जल योजना का लाभ लोगों को मिल पा रहा है। कई बार ग्राम पंचायत में मीटिंग व कैंप लगाया जाता है इस कैंप में कई बार विधानसभा स्तर के जनप्रतिनिधि व कलेक्टर तक की उपस्थिति रही है। तथा स्थानीय लोगों ने मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने हेतु अवगत भी करवाया गया। इसके बावजूद भी ग्रामवासियों को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। ग्राम का सबसे बड़ा मुद्दा था कि, शीघ्रता शीघ्र नल-जल योजना को सुचारू रूप से शुरू किया जाए लेकिन नई व तीसरे इंजन की पंचायत बाड़ी भाजपाइयों की पैनल के चार वर्ष होने के बाद भी आज तक नल जल योजना को मूर्त रूप नहीं दिया गया है।

बाजार के बीचो-बीच प्राथमिक शाला बनी हुई है के परिसर के पास हेडपंप लगा है जहां पूरे बाजार व आसपास फलीये के लोग पानी भरने आते हैं। साथ ही उक्त स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी पानी पीने आते हैं। लेकिन उक्त हेडपंप के पास बनी गटर में ही कूड़े करकट का ढेर लगा हुआ है। कचरे के कारण पूरी गटर जाम हो जाती है वहीं बारिश के मौसम के चलते तथा नालियों में गंदगी के चलते मच्छरों की तादाद बढ़ने के चलते गंभीर बीमारियों की संभावना हो जाती है।

वैसे तो ग्राम पंचायत, ग्राम के रहवासियो से उनके घरों से ट्रैक्टर के माध्यम से कूड़ा कचरा ले जाती है लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा नालियों व सड़क की सफाई करवाकर नियमित रूप से कचरा ले जाने में असमर्थ ही साबित हो रही है। नतीजन नालियों में कचरा कूड़ा भर जाने के साथ ही सड़कों पर भी कूड़ा-कचरा पसरा हुआ देखा जा सकता है। इतना ही नहीं ग्राम की सुंदरता की हकीकत किस तरह की होगी यह ग्राम पंचायत के आगे परिसर में पिछले 6 वर्षों से अधूरी पड़ी चार दुकानों में देखी जा सकती है। जहां ग्राम पंचायत के नुमाइंदे सार्वजनिक जगह पर शौचालय की व्यवस्था नहीं कर पाए लेकिन ग्राम पंचायत के नुमाइंदे पंचायत की बनी अधूरी दुकानों में लोगों को खड़े-खड़े मुतवा रही है तथा गंदगी पसरा रखी है। जो फोटो की मुंह जुबानी माही की गूंज के पास हे। जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि, जो पंचायत अपने परिसर में बनी अधूरी दुकानों में लोगों को मुतवा रही है व गंदगी फैला रखी है। इस पंचायत के नुमाइंदे के रहमों-करम से ग्राम की सुंदरता व विकास किस स्तर का होगा यह सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है।

पंचायत के आगे परिसर में बनी अधुरी दुकानो में लोगो को मुतवा रही ग्राम पंचायत और पसरा रखी गंदगी।

ग्राम के मुख्य मार्ग पर हेडपंप के पास सड़क पर पसरी गंदगी व नाली जाम।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422